F. No. 9-2/2024-MPS-ES
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Economics, Statistics & Evaluation Division
(MSP Section)

Krishi Bhawan, New Delhi
Date: 18th September, 2025

To,

Shri Siddharth Joshi
339, 7th Main, 3rd Cross,
Vivek Nagar, Bengaluru,
Karnataka-560047

Subject: RTI Application of Shri Siddharth Joshi vide Registration No. DOA&C/R/E/25/01479/1 dated 01.09.2025-reg.

Sir,

Please refer to your RTI application vide Registration No. DOA&C/R/E/25/01479/1 dated 01.09.2025. The requisite information in respect of aforesaid RTI Application is as under:

Information sought	Information provided
Please provide a copy of the Report of the Committee constituted by the Department of Agriculture and Cooperation in 2013 under the Chairmanship of Shri Ramesh Chand to examine the methodological issues in fixing Minimum Support Price vide No. A-49011/2/2013-EA.	A copy of the said report is enclosed with this letter.

2. The first appeal, if any, against the reply may be made within 30 days of the receipt of the reply to Shri Dhananjay Prasad Srivastava, Adviser & Appellate Authority, Room No. 11, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.

Enclosure: As above.

Yours sincerely,

18.09.2025
(Gyanendra Singh)
CPIO & Additional Statistical Adviser

Copy to: Under Secretary, RTI Cell, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.

न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करने में प्रणाली तंत्र की जांच करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट

Report of the Committee to Examine Methodological Issues in Fixing Minimum Support Prices

मार्च, 2015

March, 2015

सत्यमेव जयते

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

Department of Agriculture and Cooperation

Ministry of Agriculture, Government of India

New Delhi

न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करने में प्रणाली तंत्र की जांच करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट

विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
	आभार	I
1	प्रस्तावना	2-5
2	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अधिदेश	6-10
3	लागत अवधारणा तथा अध्यारोपण	11-20
4	प्रशुल्क, कर, ऋण व मण्डी	21-25
5	अन्य कोई संबंधित मामले	26-27
6	अनुशंसाएं	28-34
अनुलग्नक		
I	समिति का गठन तथा विचारणीय विषय	A-1 to A-3
II	बैठक का कार्यवृत	A-4 to A-14

आभार

न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में प्रयुक्त कार्य प्रणाली, कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) के विचारार्थ मुद्दों तथा इससे संबंधित अन्य पहलुओं की जांच करने के लिए समिति को अवसर प्रदान करने के लिए समिति कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को हार्दिक धन्यवाद देती है ।

समिति के सभी सदस्यों को विचार-विमर्श में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए तथा रिपोर्ट तैयार करने में मूल्यवान सुझाव देने के लिए धन्यवाद देती है । समिति कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मूल्यवान सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए इनकी प्रशंसा को अभिलेखों में दर्ज किए जाने की इच्छुक है । इन विभागों द्वारा प्रदान की गई सामग्री विषयगत मामले पर गहराई से विचार-विमर्श किए जाने में अत्याधिक मूल्यवान थी ।

इस रिपोर्ट को तैयार किए जाने में श्री आशीष बहुगुणा, निवर्तमान सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा गहरी दिलचस्पी लेने के लिए समिति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है । समिति के सदस्यों में लाजवाब सामंजस्य स्थापित करने तथा विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त को तैयार करने के लिए समिति श्री एस. आर. जोशी, सलाहकार (लागत), सीएसीपी को धन्यवाद देती है ।

समिति बैठक के कार्यवृत्त् और समिति की रिपोर्ट के हिन्दी रूपान्तरण के लिए पहल और किये गये प्रयासों के लिए सदस्य सचिव और उनकी टीम के प्रति बेहद आभारी है ।

समिति बैठकों का आयोजन करने तथा संभार तंत्र की व्यवस्था करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के सीएसीपी के लागत प्रभाग तथा ईए प्रभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देती है ।

30
मार्च, 2015

रमेश चन्द

(प्रो0 रमेश चन्द)
समिति अध्यक्ष

प्रस्तावना

पिछले तीन दशकों में कृषि उत्पादन, विपणन और व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । दो उपाख्यान जिनका कृषि के लगभग सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है वे हैं (क) देश में आर्थिक उदारीकरण जो वर्ष 1991 में शुरू हुआ तथा (ख) वर्ष 1995 में डब्ल्यूटीओ का गठन किया जाना तथा कृषि को व्यापार तथा टैरिफ पर सामान्य करार के तहत लाना । तथापि, कई अन्य घटकों के कारण भी कृषि में परिवर्तन आया है जिनमें अधिकांश में कृषक आजीविका और आय के लिए मूल्य नीति के कुछ निहितार्थ हैं ।

उत्पादन पैटर्न नकदी फसलों की ओर अग्रसर हुआ है तथा कई फसलें जिन्हें पहले जीविका की फसलें माना जाता था या पारिवारिक आवश्यकता को पूरा करने वाली फसलें माना जाता था, उन्हें अब नकदी महत्व के आधार पर उगाया जाता है । उत्पादन में लगभग सभी फसलों का विपणित अधिशेष का अनुपात बढ़ा है । खरीदे गये आदानों के उपयोग, पारिश्रमिक श्रम से पारिवारिक श्रम के प्रतिस्थापन, श्रम के पूंजी और मशीनरी से प्रतिस्थापन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में वृद्धि से उत्पादन का अत्यधिक वाणिज्यीकरण हो गया है। उन्नत प्रौद्योगिकी के अपनाये जाने से प्राय: अधिक लागत पर मण्डी से खरीदे गये बीजों का उपयोग आवश्यक हो गया है । मूल्य परिवर्तन प्रभाव निरंतर और गंभीर हो गये हैं । आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारिवारिक व्यय को पूरा करने का दबाव किसानों को कर्ज ली गई निधियों का उपयोग करके जोखिम खतरों को अपनाने को मजबूर कर रहा है । मण्डी ताकतें और मूल्यों के घटने की स्थितियां कृषि संबंधी दबाव तथा कृषक आत्महत्याओं जैसी स्थितियों का कारण बन रही है ।

देश में अनुसरण किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर आधारित वर्तमान प्रणाली से किसानों का मोह भंग हो रहा है । दूसरी तरफ धान, गेहूं, कपास, गन्ना, पटसन और नारियल को छोड़कर यह सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं है कि किसानों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मूल्य एमएसपी से कम न गिरें । यहां तक कि धान, गेहूं और कपास के मामले में भी

न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल कुछ राज्यों में ही प्रभावी है जहां सार्वजनिक खरीद प्रणाली मौजूद है । अन्य स्थानों में किसानों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वास्तविक मूल्य कई मामलों में एमएसपी से कम होता है । इसी तरह से अनेक मण्डियों में अन्य अनाजों, दलहनों और तिलहनों के खेती की उपज मूल्य प्राय: उनके एमएसपी से कम रहते हैं ।

विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी पर पहुंचने के लिए सीएसीपी द्वारा उपयोग किये जाने वाले कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाये गये हैं । आम मान्यता है कि उत्पादन की प्रति यूनिट खेती की लागत एमएसपी के बारे में अपनी सिफारिश पर पहुंचने के लिए सीएसीपी द्वारा उपयोग का एकल मापदण्ड है । यही कारण है कि विभिन्न किसान संगठन लागत कार्यप्रणाली, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा एकत्रित डाटा की सटीकता और विश्वसनीयता का विरोध करते हैं । किसान आयोग जैसी उच्च स्तरीय समितियों द्वारा कुल औसत भारित लागत में 50% अधिक पर एमएसपी निर्धारित करने के सुझाव दिये गये हैं । तमाम राज्यों की लागत में काफी अंतर है और कुछ राज्यों के लिए एमएसपी का विशेष स्तर उत्पादन की औसत लागत से 50% अधिक तथा अन्य कुछ राज्यों में कम हो सकते हैं, तथापि उत्पादन की औसत लागत पर पहुंचने के लिए राष्ट्रीय भारित औसत का प्रयोग होता है ।

अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसानों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मूल्यों को भी फार्म हार्वेस्ट मूल्यों पर एमएसपी के प्रभाव के अलावा और अधिक मजबूती से प्रभावित करते हैं । यह विशेष रूप से ऐसी फसलों और किसानों के लिए सच है जो एमएसपी से सीधे लाभान्वित नहीं है। इन घटकों में शामिल हैं प्रशुल्क (टैरिफ), संस्थागत ऋण पर ब्याज दर, आदान राजसहायता, कराधान ढ़ांचा, अवसंरचना, मण्डी विनियमन, बाजार विकास का चरण तथा बाजार प्रतिस्पर्धा। कुछ मामलों में यदि नीतिगत परिवेश अनुकूल हो तो किसान एमएसपी से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं । इसके विपरीत, प्रतिकूल नीतिगत परिवेश किसानों के लिए विनाशक हो सकता है । इस तथ्य के बावजूद, किसानों के लिए बेहतर ट्रीटमेंट प्राप्त करने हेतु सबसे अधिक ध्यान मूल्यों पर केन्द्रित किया जा रहा है । आंशिक रूप से इसका कार्य होने के कारण तथा आंशिक रूप से ऐतिहासिक विरासत के कारण यह कार्य विशेष रूप से सीएसीपी को दिया गया है । इस तरह से, फार्म मूल्यों पर अन्य नीतियों तथा उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की स्थिति में सीएसीपी की भूमिका को देखना प्रासंगिक है ।

इस पृष्ठभूमि में (i) सीएसीपी के विद्यमान कार्य, (ii) एमएसपी के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं, (iii) किसानों को प्रभावित कर रही अन्य नीतियां तथा फार्म उत्पाद के मूल्यों की जांच करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1

अप्रैल, 2013 को एक समिति गठित की गई थी । समिति के विशिष्ट विचारार्थ मुद्दे इस प्रकार हैं:

क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के वर्तमान अधिदेश की समीक्षा करने और यह सुझाव देना कि क्या उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की स्थिति में तेजी से बदल रहे बाह्य परिवेश का सामना करने के उपाय करके इसके अधिदेश और छोड़ने के संबंध में आयोग के पुनर्स्थीकरण की जरूरत है ।

ख) न्यूनतम समर्थन मूल्यों को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ विद्यमान लागत अवधारणा की जांच करने तथा एमएसपी के निर्धारण के लिए परिवहन, विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण आदि की लागत सहित विभिन्न घटकों का सुझाव देना । इसके अलावा समिति (i) पारिवारिक श्रम; (ii) भूमि का किराया मूल्य; (iii) ब्याज या पूंजी; (iv) ट्रैक्टर, बैल आदि जैसी निर्धारित मदों का मूल्य ह्रास के मूल्य गणना में अनुसरण की गई विद्यमान पद्धतियों के औचित्य का विश्लेषण तथा सुधार के उपायों की सिफारिश भी करेगी ताकि उन्हें और अधिक यथार्थवादी बनाया जा सके ।

ग) प्रशुल्क, करों, ऋण, मण्डी आदि के विद्यमान ढ़ांचे की जांच करना तथा व्यापार उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की स्थिति में इसे सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी और किसानों के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देना और साथ ही कृषि वृद्धि को प्रोत्साहित करना ।

घ) किसी अन्य संबंधित और प्रासंगिक मामलों की जांच करना जो सिस्टम में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हों ।

समिति का गठन

प्रो० रमेश चन्द, निदेशक, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान, नई दिल्ली की अध्यक्षता में सरकार द्वारा समिति गठित की गई और इसके सदस्य शिक्षा, कृषक संगठनों, सीएसीपी, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा कृषि मंत्रालय से हैं । विचारणीय विषय के साथ समिति का संविधान अनुलग्नक-I पर है।

कार्य प्रणाली

समिति ने पांच बैठकें की जिनमें टीओआर को शामिल करते हुए विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । समिति के सदस्य एमएसपी की सिफारिशों पर पहुंचने के लिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण और प्रक्षेपित लागत आकलन के लिए मुख्य फसलों की खेती की लागत और अपनाए गए तरीकों के लिए व्यापक योजना के विस्तृतिकरण द्वारा लाभान्वित हुए थे । विभिन्न बैठकों का कार्यवृत्त अनुलग्नक-II पर है ।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अधिदेश

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के विचारणीय विषय में अधिदेश अभिव्यक्त है जिनकी आवधिक समीक्षा की जाती है । आयोग की स्थापना उस समय के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के संकल्प द्वारा 1965 में की गई थी और इसका नाम कृषि मूल्य आयोग रखा गया । संकल्प के अनुसार आयोग की स्थापना एक संतुलित और समेकित मूल्य संरचना विकसित करने के लिए और इसका अधिदेश 11 कृषि फसलों/फसल समूहों की मूल्य नीति पर सलाह देना था । तदन्तर वर्ष 1985 में आयोग का वर्तमान नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग(सीएसीपी) हुआ । वर्ष 2009 में अधिसूचित सीएसीपी के लिए वर्तमान विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं (सीएसीपी विमर्श पत्र 7,2013):

1. धान/चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, तूर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन बीज, रैपसीड और राई, कपास, जूट, तम्बाकू, तिल, रामतिल, मसूर, कुसुम, कोपरा और ऐसे अन्य जिंसों की मूल्य नीति पर सलाह देना जिनका सरकार अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संतुलित और समेकित मूल्य संरचना को तैयार करने के मद्देनजर और उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों के लिए समय-समय पर निर्धारण कर सकती है ।

2. मूल्य नीति और संबंधित मूल्य अवसंरचना की संस्तुति करते हुए आयोग निम्नलिखित को ध्यान में रखे:
   i) उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन पद्धति को व्यापक रूप से अपनाना ।
   ii) भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।

iii) शेष अर्थव्यवस्था विशेषत: जीवन स्तर, मजदूरी स्तर, कृषि आधारित उत्पादों की लागत संरचना और कृषि एवं कृषि आधारित जिंसों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर मूल्य नीति के होने वाले प्रभाव ।

3. आयोग ऋण नीति, फसल और आय बीमा और अन्य क्षेत्रों से संबंधित ऐसे गैर मूल्य उपायों के लिए भी सुझाव दे सकता है ताकि उपर्युक्त 1 में तय उद्देश्यों की उपलब्धियों को सरल बनाया जा सके ।

4. मूल्य नीति को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपायों, विभिन्न कृषि जिन्सों के संबंध में समय-समय पर संस्तुति करना ।

5. कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में परिवर्तन करना ।

6. विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जिंसों की विपणन लागत और वर्तमान तरीकों का निरीक्षण करना, जहां आवश्यक हो, विपणन की लागत कम करने के लिए उपाय सुझाना और विपणन के विभिन्न स्तरों के लिए उचित मूल्य मार्जिन संस्तुत करना ।

7. विकासमान मूल्य स्थिति पर निगाह रखना और समग्र मूल्य नीति के फ्रेमवर्क में यथा आवश्यक उचित सिफारिशें करना ।

8. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित विभिन्न फसलों के संबंध में अध्ययन कराना ।

9. मूल्य नीति के संबंध में अध्ययनों को समीक्षाधीन रखना तथा कृषि मूल्यों और अन्य संबंधित डाटा के संबंध में सूचना के संग्रह के लिए प्रबंध करना तथा उक्त के लिए सुधार सुझाना एवं मूल्य नीति के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना ।

10. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित कृषि मूल्यों और अन्य उत्पादन से संबंधित किसी समस्या पर सलाह देना ।

11. संस्तुत गैर मूल्य उपायों के साथ मूल्य संस्तुति का प्रभावी समेकन करना और प्रतिस्पर्धी कृषि सुनिश्चित करना ।

उपर्युक्त उद्धृत विचारणीय विषय बहुत बड़े पहलुओं को कवर करता है और पूर्णतया व्यापक है। समिति की आम भावना है कि इन विचारणीय विषय को उत्पादकों, उपभोक्तओं और समग्र अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी के बारे में संस्तुति करने के लिए सीएसीपी की आवश्यकता है । आयोग कृषि संगठनों/समितियों के प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार विमर्श करता है और मूल्य नीति रिपोर्ट बनाने के लिए किसानों से संबंधित विभिन्न तत्कालीन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों का दौरा भी करता है । मूल्य नीति की सिफारिशें करते समय सीएसीपी किसानों के लाभ को प्राथमिकता देता है ।

समिति ने नोट किया है कि सीएसीपी के मौजूदा विचारणीय विषय में उत्पादन, संतुलित वृद्धि, सततता, फसल समानता और कुछ अन्य आर्थिक पहलुओं का प्रोन्नयन करना है जोकि बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण है परन्तु यह किसानों से संबंधित चिंताओं जैसे खेती की व्यवहार्यता, लाभ, खेती आय की पर्याप्तता, कृषि और गैर कृषि आय के बीच विषमताएं, खेती का आधुनिकीकरण, कृषि संरचना, आदान मूल्य, बाजार विकास और कृषि एवं कृषि संबंधितों को प्रभावित करने वाले विभिन्न अन्य पहलुओं से संबंधित कृषक मुद्दों के बारे में पूरी तरह से मौन है। यह सभी पहलू कृषि में रूचि बनाये रखने और किसानों को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण है ।

विचारणीय विषय 4 यह चाहता है कि मूल्य नीति को प्रभावी बनाने के लिए सीएसीपी समय-समय से संस्तुति करे । आयोग ने मांग-आपूर्ति और मूल्य नीति की प्रभावकारिता जिसमें एमएसपी के साथ फसलों के डब्ल्यूपीआई की तुलना, खरीद नीति और इसके प्रचालन, इसकी विभिन्न मूल्य नीति रिपोर्टों में बाजार विरूपण शामिल हैं, का पूरा अध्याय लिया है । इन रिपोर्टों में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में अतिरिक्त खरीद केन्द्रों की स्थापना की आयोग ने सिफारिश की है । तथापि सीएसीपी की यह गैर मूल्य सिफ़ारिशें मुश्किल से सरकार का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं क्योंकि आयोग को केवल मूल्य नीति पर सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने वाला ढांचा माना जाता है । यह आम बात है कि मूल्य नीति केवल कुछ फसलों नामत: धान/चावल, गेहूं, कपास और गन्ने के लिए ही प्रभावी है । यहां तक कि धान/चावल और गेहूं के मामले में एमएसपी सभी बाजारों में प्रभावी न होकर केवल कुछ राज्यों में प्रभावी है जहां सरकार द्वारा खरीद होती है । विभिन्न राज्यों के अनेक बाजारों में किसानों को एमएसपी से कम मूल्य प्राप्त होता है । यह योजना आयोग के कागजातों और यहां तक कि सीएसीपी की रिपोर्टों में भी पाया गया है । इसके लिए ठोस और सुदृढ तंत्र की आवश्यकता है

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम किसान को वह मूल्य प्राप्त हो जिसका एमएसपी के रूप मे आश्वासन दिया गया है |

सीएसीपी यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का सुझाव और संस्तुति देनी चाहिए कि जब फसल मौसम में बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो तो किसानों को उनके बाजार अधिमान पर मौद्रिक हानि के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाये । यह स्वभाविक है कि खरीद प्रणाली के माध्यम से एमएसपी सभी जगह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता इसलिए मूल्य सुरक्षा के लिए कमी मूल्य भुगतान अथवा मूल्य बीमा जैसा वैकल्पिक तंत्र उन सभी फसलों के लिये जिनका एमएसपी घोषित होना चाहिए, हालांकि डी०इ०एस० ने यह अंकित किया है कि मूल्य कमी भुगतान तंत्र भारत में ठीक नहीं है क्योंकि यह उन देशों में प्रचलित है जहां दो या तीन फ़सलें कवर की जाती हैं | मूल्य कमी तंत्र को भारत नहीं अपना सकता जहां एम०एस०पी० अंतर्गत 23 फ़सलें आती है | जहां भी बाजार भाव एम०एस०पी० से नीचे जायें वहां सरकारी खरीद को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे किसानो को एम०एस०पी० सुनिश्चित हो सके। डी०इ०एस० के अनुसार जहां भी ऐसी जरूरत हो वहां सरकारी खरीद करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए।

समिति यह महसूस करती है कि सीएसीपी को सभी राज्यों में सभी महत्वपूर्ण फसलों के लिए विपणन मौसम में खेत कटाई मूल्यों का मानिटरिंग करना चाहिए | यह ध्यान में रखने के लिए कि किसानों को एमएसपी से कम मूल्य न प्राप्त हो, यदि ऐसा होता है तो सीएसीपी को इस स्थिति को नियन्त्रण में रखने के लिए सरकार को तुरन्त सिफारिश करनी चाहिए | सीएसीपी को मूल्यों के वार्षिक समीक्षा तथा कृषि तथा किसानों से प्रभावित विभिन्न नीतियों का प्रकाशन करना चाहिए जिसको बजट सत्र में संसद में रखा जाना चाहिए । तथापि डी०इ०एस० का यह मानना है कि सीएसीपी की रिपोर्ट को संसद में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है | सीएसीपी से संबंधित विविध मामलो पर विविध सिफ़ारिशें कृषि की संसदीय स्थायी समिति, मांग एवं अनुदान संसदीय समिति और अन्य इस तरह की समितियों में विस्तार से विचार विमर्श करती है |

कुछ पहलू जो उत्पादकों के हितों से बुरी तरह टकराते हैं, मौजूदा विचारणीय विषय के तहत अभी भी कवर नहीं होते है । इनमें से निर्यात/आयात विनियमन तथा टैरिफ को कवर करते हुए व्यापार नीति सबसे महत्वपूर्ण है । व्यापार उदारीकरण और भौगोलीकरण के साथ व्यापार नीति के अवयवों ने खेती के मूल्यों को बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया है|

सीएसीपी कृषि उत्पादों पर व्यापार अधिनियमन के संबंध में कोई भूमिका अदा करता नहीं दिखाई देता है । प्रशुल्क, आयात एवं निर्यात के निर्णय आम तौर पर उपभोक्ताओं और उद्योग के हितों के आधार पर लिए जाते हैं । बहुत बार इससे उत्पादकों को बहुत अधिक मूल्य आघात होता है । घरेलू मूल्य अधिक होने पर कृषि निर्यात पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाना बिल्कुल आम हो गया है । तथापि कृषि क्षेत्रों और उत्पादकों की जरूरतों को देखते हुए आयात को सख्ती से नियंत्रित नहीं किया जाता है | समिति यह महसूस करती है कि सभी व्यापार नीति निर्णयों मे सीएसीपी से विचार विमर्श करना चाहिए

उद्योग और अन्य क्षेत्रों के पास मजबूत व्यवसायिक निकाय यथा एफआईसीसीआई, सीआईआई, एएसएसओसीएचएएम, पीएचडीसीआई हैं जो उनकी हित चिंताओं को स्पष्ट करते हैं और नीतियों को उनके पक्ष में करने के लिए लॉबी करते हैं । कृषि क्षेत्र तथा कृषकों के हितों को स्पष्ट करने के लिए व्यवसायिकों के साथ कोई ऐसा भारतीय पटल अथवा क्षेत्रीय व्यवसायिक निकाय नहीं है ।

सीएसीपी कृषकों और कृषि क्षेत्र की चिंताओं को बताने वाला और किसानों के हितों की रक्षा करने वाला उचित निकाय है । समिति संस्तुत करती है कि सीएसीपी की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए और इसका नाम 'कृषि लागत, मूल्य और नीति आयोग' होना चाहिए। खाद्य कृषि और किसानों पर विभिन्न नीतियों के विश्लेषण के लिए उचित स्टाफ के साथ सीएसीपी में उच्च स्तर पर व्यवसायिक विशेषज्ञ होने चाहिए । आयोग को (1) कृषि व्यवस्था, खाद्य मूल्य और (2) उभरती परिस्थितियों में नीति सिफारिशों की सूची के साथ किसानों की स्थिति पर तिमाही रिपोर्ट को सीएसीपी की मूल्य नीति की रिपोर्ट की तरह मंत्रीमंडल के समक्ष इसको कार्यान्वित करने के लिए रखा जाना चाहिए | यह भी सिफारिश की जाती है की सीएसीपी को बजट पूर्व मंत्रणा में शामिल करना चाहिए, आयोग को केन्द्रित रूप से किसानों की आय बढाने के लिए विशिष्ट नीतियोंकी सिफ़ारिशें करनी चाहिए | तथापि डी०इ०एस० का यह मानना है कि नीतियों का निर्धारण सरकार का अधिदेश है और इसे आयोग को नहीं दिया जा सकता है और सुझाव है कि सीएसीपी द्वारा नीति निवेशों पर मूल्य नीतियों पर दी गई रिपोर्टों जिनमे मूल्यगत और गैर मूल्यगत दोनों सिफ़ारिशें शामिल होती हैं को सरकार द्वारा यथोचित मान देना चाहिए |

लागत अवधारणा तथा अध्यारोपण

आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर एवं अन्य गैर-मूल्य उपायों के संबंध में विशिष्ट जिंसों या जिंसों के समूह का समग्र आर्थिक संरचना व्यापक दृष्टिकोण के अलावा ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित घटकों पर अपनी सिफारिशें बनाती हैं:

(i) उत्पादन लागत
(ii) आगत कीमतों में परिवर्तन
(iii) आगत-उपज मूल्य समता
(iv) बाजार मूल्यों की प्रवृतियाँ
(v) मांग और आपूर्ति
(vi) अंतर फसल मूल्य समता
(vii) औद्योगिक लागत ढांचे पर असर
(viii) जीवन यापन लागत पर असर
(ix) सामान्य मूल्य स्तर पर असर
(x) अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिस्थितियां
(xi) किसानों द्वारा प्रदत मूल्य एवं प्राप्त मूल्य पर समता
(xii) जारी मूल्यों पर प्रभाव और सब्सिडी निहितार्थ

खेती लागत/उत्पादन लागत का आकलन, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशें गठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदान, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित, मुख्य फसलों की खेती लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक स्कीम के माध्यम से मूल्य आयोग को उपलब्ध कराया जाता है । ये आकलन खेती के वास्तविक घटकों पर विचार करती है तथा उत्पादन, भूमि के पट्टे के लिए किराया भुगतान, परिवार श्रम का अध्यारोपित मूल्य, स्वामित्व पूंजी सम्पति (भूमि

छोड़कर) का ब्याज मूल्य, कृषि उपकरणों एवं भवनों एवं अन्य विविध व्यय पर मूल्य ह्रास में किसानों द्वारा किये गये श्रम, नकदी एवं प्रकार में सभी वास्तविक व्यय शामिल करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए उपयोग किये गये विभिन्न लागत अवधारणाओं का नाम पद्धति एवं शब्दावली निम्नानुसार है:

<u>भुगतान की गई लागत</u>

i. किराये पर लिये गये श्रमिक (मानव, पशु एवं मशीन)
ii. स्वामित्व पशु एवं मशीनों पर रख-रखाव खर्च
iii. सामग्री आदानों जैसे बीज (देशी एवं खरीद की गई), उर्वरक, खाद (स्वामित्व एवं खरीद की गई), कीटनाशी, कृमिनाशी, खरपतवारनाशी एवं सिंचाई पर व्यय
iv. औजार एवं फार्म भवन मूल्य में कमी (जैसे पशु शेड, मशीन शेड, भंडारण शेड) पर मूल्य ह्रास
v. भू-राजस्व एवं अन्य कर
vi. विविध कार्य
vii. पट्टे की भूमि के लिए किराया भुगतान

<u>अध्यारोपित लागत</u>

i. परिवार श्रम का मूल्य
ii. स्वामित्व भू का किराया; और
iii. अपने द्वारा निर्धारित पूंजी एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

निम्नलिखित मानक लागत अंकन उपयोग किये जाते हैं:

लागत ए1: मालिक प्रचालकों द्वारा उत्पादन में किये गये नकद एवं अन्य प्रकार के सभी वास्तविक खर्च ।

लागत ए2: लागत ए1 + पट्टे पर भूमि के लिये भुगतान किया गया किराया ।

लागत बी1: लागत ए1 + स्वामित्व पूंजी सम्पति (भूमि को छोड़कर) का मूल्य पर ब्याज

लागत बी2:	लागत बी1 + स्वामित्व भू (भू-राजस्व का निवल) का किराया मूल्य तथा पट्टे पर भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया ।
लागत सी1:	लागत बी1 + परिवार श्रम का अध्यारोपित मूल्य
लागत सी2:	लागत बी2 + परिवार श्रम का अध्यारोपित मूल्य
लागत सी3:	किसान के प्रबंधकीय आदानों के लिए खातों में लागत सी2 सहित लागत सी 2 का 10 प्रतिशत ।

सामान्यत: उत्पादन लागत (सी 2) न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशें तैयार करने में एक महत्वपूर्ण आदान के रूप में विचार किया जाता है । जहां तक उत्पादन से संबंधित है, यह एक व्यापक लागत है तथा यह भुगतान किये गये लागत तथा आदानों के अध्यारोपित मूल्य, सेवाएं तथा फार्म परिवार जैसे परिवार श्रम का अभिकलन, किसानों की अपनी पूंजी का उपयोग एवं फसल उत्पादन कार्यकलाप के लिए अपनी भूमि का उपयोग द्वारा संसाधनों का योगदान या स्वामित्व को शामिल करती हैं । परिवार द्वारा योगदान की गई आदानों को तृतीय पक्ष या बाजार में विभाजित नहीं किया जाता है, उनकी लागत अभियोग पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हैं । इसलिए यहां तक कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत सी 2 के बिल्कुल समान है, अध्यारोपित पारिवारिक श्रम, निर्धारित पूँजी पर ब्याज एवं स्वामित्व भूमि का किराया जो कि किसान द्वारा नकद एवं अन्य प्रकार के वास्तविक खर्च के रूप में किसानों को कुछ आय प्राप्त हो जाती है ।

किसान अपने समय का उपयुक्त मूल्यांकन, अपनी भूमि का किराया मूल्य, पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास आदि मुद्दे को उठाता रहा है तथा इन मदों का यथार्थवादी उपचार मांगता रहा है।

पारिवारिक श्रम का अभिकलन

पारिवारिक श्रम लागत स्थानीय मजदूरी दर अथवा वास्तविक बाजार मजदूरी दर जो अधिक हो, के आधार पर अभिकलन किया जाता है । इस प्रकार के उपचार निर्णय लेने, जोखिम लेने एवं अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता की शर्त पर किसानों के कौशल मूल्य आकलन नहीं होता है| योजना बनाने में, सामान्य देखरेख, आदानों की व्यवस्था करने के लिए दौरा एवं फार्म व्यवसाय के लिए अन्य स्रोत, फार्म से संबंधित सामान्य कार्यकलाप में भागीदारी पर किसानों द्वारा दिया गया समय भी जोड़ा नहीं जाता है । समिति के विभिन्न सदस्यों ने देखा कि

किसानों के कौशल और नवीनता को श्रमिक मजदूरी के अभियोग में उपयुक्त महत्व नहीं दिया जा रहा हैं | इसलिए समिति महसूस करती है कि किसानों द्वारा केवल उत्पादन में निरंतर समय लगाना और सामान्य श्रमिक की मजदूरी दर से इसका मूल्यांकन करना किसान के समय का बहुत कम मूल्यांकन है, जबकि यह अनुभव किया गया है कि किसानों को खेती के काम में विशेषज्ञ की तरह उपचारित किया जाना चाहिए | समिति ने सुझाव दिया है कि परिवार का प्रधान जो खेती में व्यस्त है, उसकी मजदूरी का आकलन कौशल मजदूरी दरों के आधार पर होना चाहिए | इसके अतिरिक्त किसानों के खतरा लाभ तथा प्रबंधकीय प्रभारों को महत्व देते हुए सी 2 लागत को 10 प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए | तथापि डीईएस इससे सहमत नहीं था और उसने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया कि पारिवारिक श्रम सहित पेड-आउट लागत (ए2+एफएल) का 10 प्रतिशत को ए2+एफएल लागत में जोड़ा जाना चाहिए ताकि किसानों का प्रबंधकीय प्रभार वहन हो सके |

स्वामित्व भूमि पर किराया

भूमि किराया समान प्रकार की भूमि के लिए गांव में प्रचलित किराए या नमूना किसानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आधार पर अनुमानित किया जाता है, जो संबंधित राज्य के भूमि विधान में दिए गए उचित किरायों की अधिकतम सीमा के अधीन है | समिति की सिफारिश हैं कि इसे प्रचलित किराया या असल किराया जो किसानों ने रिपोर्ट किये बिना उच्चतम दरें लगाये, आकलन करना चाहिए |

स्वामित्व नियत पूँजी एवं कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूँजी पर ब्याज आधी फसल अवधि के लिए 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगाया जाता है और निमत सम्पत्ति की वर्तमान कीमत पर ब्याज 10 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है | ये ब्याज दर संस्थागत स्त्रोतों द्वारा लगाए गए ब्याज के संदर्भ में है | कई बार किसान संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं या संस्थागत ऋण पर्याप्त नहीं होते हैं, और वे गैर संस्थागत स्त्रोतों से उधार लेते हैं तथा अधिक ब्याज दरें अदा करते हैं | चूँकि खेती लागत प्रश्नावली में ऋण के स्रोत और उस पर प्रदत्त ब्याज पर सूचना शामिल होती है, इसलिए स्वामित्व नियत पूँजी और कार्यशील पूँजी पर ब्याज की कीमत लगाने के लिए ऋणी नमूना किसानों द्वारा संस्थागत और गैर संस्थागत ऋणों पर प्रदत्त वास्तविक ब्याज लगाना उचित होगा |

यह दिखाई पड़ता है कार्यशील पूँजी पर आधे फसल मौसम के लिए ब्याज चार्ज करना आदान के उपयोग से मेल खाते संसाधनों के सही प्रवाह पर आधारित है । यह कृषि में नहीं हो पाता है । अल्पावधि या फसल ऋण फसल की बुवाई के समय पर लिए जाते हैं और फसल कटाई के बाद लौटाया जाता है । इस प्रकार ब्याज पूरे फसल मौसम के लिए दिया जाता है । अत: यह सुझाया जाता है कि कार्यशील पूँजी पर ब्याज आधी फसल अवधि के लिए नहीं अपितु पूरी फसल अवधि के लिए अनुमानित किया जाए।

प्रसंस्करण, परिवहन और विपणन लागत

सीएसीपी रिपोर्टो और डीइएस की खेती लागत रिपोर्टो में प्रस्तुत खेती लागत आंकड़ों में विक्रय वसूली से पूर्व किसानों द्वारा उठाई गई सफाई, ग्रेडिंग, सुखाई, पैकेजिंग, विपणन और मण्डी तक उत्पाद के परिवहन जैसी फसल पश्चात लागतें शामिल नहीं करता है । तथापि ऐसी लागतें सीओसी स्कीम की प्रश्नावली में शामिल की गई है । समिति ने सिफारिश की है कि यह लागतें सीओसी के भाग के रूप में होनी चाहिए । यह भी सिफारिश की जाती है कि खेती की सी2 लागत पर पहुंचने के लिए समुचित जोखिम मार्जिन को जोड़ा जाना चाहिए । तथापि, इस मुद्दे पर डीईएस ने रेखांकित किया कि सीओसी एक्स-फार्म लागत है तथा इसकी गणना रू0/है0 में की जाती है, जबकि विपणन एवं परिवहन लागत फसलोपरांत लागत है और इनकी गणना रू0/क्विंटल में की जाती है । अत: ऐसी लागत सीओसी का भाग नहीं हो सकतीं । यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सीएसीपी को लागत अनुमान भेजे जाते समय इन लागतों को अलग से इंकित किया जाना चाहिए तथा सीएसीपी एमएसपी के विचार के समय इन लागतों को सी2 लागत में जोड़े |

लागत प्रक्षेपण

फसल का उत्पादन और उपज किसी भी मौसम का न्य.स.मू. की घोषणा के समय पर ज्ञात नहीं होता है । लागत आंकड़े 2-3 वर्ष के अन्तराल पर प्राप्त होते है उदाहणार्थ विपणन वर्ष 2014-15 के लिए घोषित किए गए न्यू.स.मू. हेतु सीओसी डाटा अंतिम रूप में वर्ष 2011-12 तक उपलब्ध रहेगा | इसमें कुछ अन्तराल स्पष्ट है । इस प्रकार सीएसीपी वर्ष टी-3 के आधार डाटा और विभिन्न आदानों में स्फीति दर पर आधारित वर्ष टी-3 के लिए लागत डाटा प्रक्षेपित करता है । ऐसा करने में, सीएसीपी मानता है कि नियत लागत अल्पावधि में नहीं बदलती है और संयुक्त परिवर्तनीय आदान सूचकांक (सीवीआईआई) तैयार करने के लिए एक

जटिल कार्य प्रणाली का प्रयोग करता है । इस सूचकांक के घटकों में मानव श्रम (एचएल), बैल श्रम (बीएल), मशीन श्रम (एचएल), बीज, उर्वरक, खाद, कृमिनाशक और सिंचाई प्रभार शामिल हैं । इस प्रणाली की दो कमियाँ नीचे दी गई है:

- एक स्फीतिक अर्थव्यवस्था में यह मानना उचित नहीं है कि नियत लागत 3 वर्षों में नहीं बदलेगी ।
- यदि प्रौधोगिकीय परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, तो उत्पाद की प्रति इकाई निविष्टि (आई/ओ) बढ़ेगी, जिससे पर्याय समय के साथ वास्तविक औसत लागत में वृद्धि होगी।

दूसरी कमी से निपटना अत्यंत कठिन है, परन्तु पहली का समाधान करना बहुत सरल है। इसका हल नियत लागत के अंतर्गत उपयुक्त चर लागतों में स्फीति की दर के अनुसार सी 2 लागत के नियत लागत घटक को बढाना है । नियत लागत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक भूमि का किराया है। अन्य घटक नियत और कार्यशील पूँजी पर ब्याज तथा फार्म परिसंपत्ति ह्रास है। समिति ने नियत लागत के विभिन्न मदों को आकलित करने के लिए निम्नलिखित कार्य प्रणाली प्रस्तावित की है:

नियत पूंजी पर ब्याज के प्रक्षेपण के संबंध में यह बताया जा सकता है कि उस अवधि के लिए इस घटक की गणना आसानी से की जा सकती है जिसके लिए ऋण लिया गया है ।

- नियत पूँजी पर ब्याज और मूल्यह्रास को निर्माण सामग्री में मुद्रास्फीति की दर से उन्हें बढा करके प्रक्षेपित किया जाए ।
- कार्यशील पूँजी पर ब्याज को संयुक्त परिवर्तनीय आदान सूचकांक के अनुसार बढ़ा करके प्रक्षेपित किया जाए।
- भूमि किराए को कृषि जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा बढ़ा करके प्रक्षेपित किया जाए जो भूमि किराए में उतार चढ़ाव का मुख्य निर्धारक है।

तथापि इस मुद्दे पर सीएसीपी ने व्यक्त किया है कि नियत लागत में नियत पूंजी पर ब्याज और स्वामित्व भूमि का किराया मूल्य शामिल होता है । नियत पूंजी पर मूल्यह्रास और कार्यशील पूंजी पर ब्याज (जो नियत लागत का भाग नहीं है) का प्रक्षेपण अलग से होता है। इसलिए स्वामित्व भूमि का किराया मूल्य और नियत पूंजी पर ब्याज पर नियत लागत के प्रक्षेपण के लिए विचार करना पड़ेगा । सीएसीपी द्वारा यह पाया गया है कि समिति द्वारा

दिये गये सुझावों को अपनाने से स्वामित्व भूमि का किराया मूल्य वास्तविक से बहुत कम है। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि सीएसीपी नियत लागत के प्रक्षेपण के लिए अलग से ऐसी पद्यति जांच सकती है जो कि वास्तविकता के नजदीक है ।

लागत का औसतीकरण

राज्यों के बीच और किसी राज्य के भीतर किसानों के बीच लागत में बहुत बड़े अन्तर हैं । सीएसीपी उत्पादन लागत को निरूपित करने के लिए सभी राज्यों में नमूना किसानों की औसत लागत का प्रयोग करता है । इसका अर्थ है कि लगभग आधे किसानों की औसत से ऊपर वास्तविक लागत रखी जाएगी और शेष आधे की औसत स्तर से नीचे रखी जाएगी । क्योंकि न्यू.स.मू. का स्तर सामान्यत: औसत सी 2 लागत से अधिक है, उन किसानों का प्रतिशत जिनकी लागत न्य.स.मू. में शामिल नहीं की जाती है, वे 50 प्रतिशत से कम हैं । सीएसीपी के एक कार्यशील कागज के अनुसार वर्ष 2010-11 में एमएसपी उत्पादन लागत (सी2) उत्पादन का 96 प्रतिशत गन्ना में, 94 प्रतिशत जौ में, 93 प्रतिशत धान में, सरसों में 92 प्रतिशत और गेहूं उत्पादन का 88 प्रतिशत कवर करती है । विगत में सुझाव दिये गये कि न्यू.स.मू. के निर्धारण के लिए औसत लागत की बजाए बल्क लाइन लागत ली जाए, कुछ ने यह सुझाव दिया कि एमएसपी निर्धारण के लिए आधार लागत के तौर पर उच्च लागत स्थिति को प्रयोग किया जाए (सीएसीपी 2008-09 की रिपोर्ट की मद सं. 4.6)| इसके लिए निर्देशित सिद्धांत किसानों की क्षमता और अधिकतम किसानों के कवरेज के बीच संतुलन बैठाना चाहिए । एक अनुभव क्षमता मानदण्ड का ऐसा औसत लेना है जो गणितीय साधन और किसानों की अधिकतम कवरेज अर्थात 100 प्रतिशत का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है कि बल्क लाइन लागत 75 प्रतिशत [(50+100)/2] किसानों को शामिल करते हुए सी2 लागत को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाए । वर्तमान में डीइएस स्थापित आकलन पद्धति से सभी फसलों का राज्यवार लागत अनुमान आकलित करती है | तथापि समिति का सुझाव है कि किसानों की अधिकतम कवरेज के लिए, डी.इ.एस बल्क लाइन लागत का विश्लेषण कर सकता है |

प्रतिदर्श (नमूनों) का आकार व प्रतिदर्श (नमूने) लेने की प्रणाली

लागत अनुमानों की विश्वसनीयता व निरूपण नमूना किसानों के चयन के लिए उपयोग किए गए नमूने के आकार व प्रणाली पर निर्भर करता है। सीओसी आंकड़ों के निरूपण व विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

1. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित मुख्य फसलों की खेती की लागत के लिए व्यापक योजना के तहत प्रत्येक चुनी हुई तहसील/ब्लाक में से वर्तमान में एक नमूना गांव का चुनाव किया जाता है । समिति ने सुझाव दिया है कि नमूना गांव की वृहद कवरेज के लिए प्रत्येक चुनी हुई तहसील/ब्लाक से एक गांव के स्थान पर दो गांव का चुनाव किया जाना चाहिए । इसके लिए नमूना माप बढ़ने के अनुरूप अधिक संसाधन और श्रम शक्ति की आवश्यकता पूरी करनी होगी जिससे कि किसानों से लागत आंकड़ों को प्राप्त करने की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके ।

2. संचालनात्मक जोतें वर्तमान 5 आकार वर्गों के वर्गीकरण के स्थान पर तीन आकार वर्गों अर्थात् 1 है0, 1-2 है0 या 2 है0 से अधिक में वर्गीकृत होनी चाहिए और प्रत्येक आकार वर्ग से चुने हुए परिवारों की संख्या क्रमश: 3, 2 और 1 अर्थात प्रत्येक गाँव से 6 इकाईयां ।

3 (क) समिति द्वारा नमूना चयन के वर्तमान तंत्र में कमियां देखी गई, जहां कुछ गौण फसलों के लिए चुना गया नमूना आकार बहुत छोटा होता है । समिति ने महसूस किया कि गौण फसलों के तहत क्षेत्र के लिए संभावना अनुपात से नमूना चुनाव कर समस्या पर काबू पाया जा सकता है । इस पर समिति ने तहसील और ब्लाक का चुनाव करते वक्त प्रत्येक जोन के तहत उप स्ट्रेटा में एक सामान्य स्ट्रेटा (मुख्य फसलों के लिए) और एक अन्य गौण फसल स्ट्रेटा के रूप में, की शुरूआत द्वारा मौजूदा नमूना डिजायन में संशोधन का सुझाव दिया है और आगे चुनी हुई तहसील में गांव का चुनाव करते समय बढ़ाया जा सकता है।

(ख) राज्य स्तर पर अनाज, दलहन और तिलहन के लिए इस समूह के तहत केवल उन्हीं फसलों का चुनाव किया जाए ताकि वे क्रमश: इन्हीं समूहों के तहत कुल क्षेत्र का कम से कम 90% क्षेत्र कवर कर सकें। पटसन, नारियल और गन्ने के लिए मुख्य उत्पादक राज्य इस तरीके से चुने जाएं कि अखिल भारतीय स्तर पर कम से कम 90% क्षेत्र कवर हो। इससे नमूने में गौण फसल उत्पादक प्रचालनात्मक जोतों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के मौके बढ़ सकते हैं। यह नमूना कार्य प्रणाली दृष्टिकोण अंतिम अपनाने से पहले पायलट आधार पर आजमाया जा सकता है।

4. संग्रहित प्राथमिक डाटा की गुणवत्ता और उचित क्षेत्र देखरेख में सुधार के लिए क्षेत्र पर्यवेक्षक और क्षेत्र अन्वेषकों/ फील्डमैन का अनुपात वर्तमान 1:10 के स्थान पर 1:6 होना चाहिए| हालाँकि, इसके लिए अतिरिक्त क्षेत्र पर्यवेक्षक की जरूरत होगी जिसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी |

5. तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए चुनिंदा किसान/परिवारों से सूचना संग्रह की वर्तमान प्रणाली अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए । सीएस के तहत सृजित लागत अनुमान प्रदान करने का समय कम करने के लिए एक अद्यतन साफ्टवेयर की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है ।

6. राज्यवार विश्वसनीय सी.ओ.सी. आंकड़ो के प्रजनन के लिए समिति कम से कम 300 प्रचालन जोत की सिफारिश करती है | लेकिन यह बताया जाता है कि नमूना माप बढने पर नमूना त्रुटि कम होगी लेकिन गैर नमूना गलती त्रुटि में बढोतरी हो सकती हैं |

7. वर्तमान में एम एस पी/एफआर पी के लिए 23 फसलों का विचार किया गया है | इनमें से कुछ फसलें उपलब्धता के विचार से गौण फसल होती है और वर्तमान नमूना बनावट मुख्यतः बड़ी फसलों पर ध्यान देता है जिसके कारण गौण फसलें नगण्य प्रेक्षण (कभी कभी शुन्य) सूचित तथा चुनी जाती है | यह तथ्य समिति द्वारा पहले ही ध्यान में रखा गया है ।

8. पीपीएस क्षेत्र के साथ फसलों के सुझाव के सम्बन्ध में ऐसा यह उल्लेखनीय है कि गौण फसल क्षेत्र के लिए व्यवहार्य नहीं हैं अगर पी.पी.एस को गौण फसल के क्षेत्रफल से अपनाया जाता हैं तो यह बहुत से ब्लाक/तहसील को चयनित होने से छोड़ सकता है

क्योंकि गौण फसलें सभी ब्लाक/तहसील में बोई नहीं जाती | तथापि समिति वर्तमान नमूना डिजाईन में सुधार, गाँव/ब्लाक जिसमें हर मंडल में सब स्ट्रेटा सामान्य (मुख्य फसलों के लिए) और गौण फसल स्ट्रेटा के चुनाव के अन्दर गाँव का चुनाव करते समय बढाया जा सकता हैं यह निश्चित तौर पर ऐसे प्रचालन जोतों को चुनने की स्थिति को बढावा देगी जहां गौण फसलें उगाई जाती हैं | नमूना प्रणाली को अपनाने से पहले पायलट आधार पर आजमाना चाहिए |

प्रशुल्क (टैरिफ), कर, ऋण व मण्डी

समिति महसूस करती है कि प्रशुल्क, कर, ऋण तथा मंडी संरचना का उत्पादन लागत तथा पैदावार मूल्य तथा परिणामी फार्म आय पर सशक्त प्रभाव है।

प्रशुल्क (टैरिफ)

भारत में कृषि उत्पादों के आयात पर पहले से ही बहुत कम वास्तविक प्रशुल्क (टैरिफ) है। यद्यपि सस्ते आयातकों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत का सीमित प्रशुल्क (टैरिफ) अधिक है। तथापि वास्तविक मूल्य काफी कम है। भारत में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अधिक होते हैं, तो शुल्क में बढ़ोतरी होती है तथा जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम होते है, तो कम प्रशुल्क दर को शामिल करते हुए विविध शुल्क नीति का अनुसरण करने की आवश्यकता है। इसके पश्चात, उन उत्पादों के आयात पर अधिक तथा स्थायी निर्भरता कम की जानी चाहिए जिसका उत्पादन देश में व्यापक स्तर पर किया जाता है।

भारत के तिलहन क्षेत्र ने आयात उदारीकरण के कारण गंभीर कमियों का सामना किया है। वनस्पति तेलों पर निम्न तथा कम होते हुए शुल्क के कारण उनके घरेलू मूल्य भारतीय उत्पादकों के लिए प्रतिकूल रहे हैं तथा इससे आपूर्ति कम हुई है। साथ ही, सीएसीपी ने तिलहन के लिए चल रहे मूल्य समतुल्यता का समाधान नहीं किया, बावजूद इसके कि ऐसा करना अनिवार्य था। इस कारण, भारत तिलहन उत्पादन बढ़ाने में शुष्क भूमि तथा सीमांत क्षेत्रों की क्षमता के दोहन के योग्य नहीं है। समिति का सुझाव है कि कच्चे तेल के साथ-साथ परिष्कृत खाद्य तेलों पर प्रशुल्क प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए तिलहन क्षेत्र को स्वीकृति देने के लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से निर्धारित किया जाए ।

निर्यात पर, भारत में कृषि उत्पादों पर कोई शुल्क व्यवस्था नहीं है। गैर-शुल्क अवरोध (बैरियर) द्वारा मनमाने ढंग से कृषि-खाद्य निर्यात को विनियमित किया जाता है। जब भी घरेलू मूल्य बढ़ने लगते हैं, कृषि निर्यात पर प्रतिबंध लग जाता है। देश में, विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात पर अक्सर रोक लगाई जाती है, जब भी घरेलू मूल्यों में अत्याधिक बढ़ोतरी की संभावना होती है। आयात तथा निर्यात नीति की निकट जांच यह दर्शाता है कि भारत ने मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक प्राथमिकता दी है तथा घरेलू मूल्यों में प्रवाह प्राय: अधिक उदारीकृत आयात तथा निर्यात पर प्रतिबंधों के लिए अग्रणी है। यह बताता है कि अधिकांश मामलों में उपभोक्ताओं के हित को उत्पादकों के हित से ऊपर रखा गया है। समिति बल देती है कि सीएसीपी से शुल्क तथा व्यापार नीति पर अनिवार्य रूप से विचार-विमर्श करना चाहिए तथा इसकी सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए।

कृषि ऋण

कृषि के बढ़े हुए व्यवसायीकरण तथा आधुनिक आदानों के प्रयोग में बढ़ोतरी के साथ, कुल उत्पादन में खरीदे गए आदानों का अंश तथा मात्रा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसके अलावा, कृषि पैदावार में बढ़ोतरी को बनाए रखने तथा उत्पादन की कुशलता के सुधार को बढ़ाने के लिए सिंचाई उपकरण, फार्म मशीनरी तथा भूमि सुधार जैसी विभिन्न प्रकार की सम्पति में निजी निवेश की भी आवश्यकता अपेक्षित है। किसानों के अपने संसाधन, कार्यकारी पूंजी तथा कृषि की निर्धारित आवश्यकताएं पूंजी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए किसानों को इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी संसाधनों से ऋण लेना पड़ता है। उद्योग के विपरीत कृषि क्षेत्र संसाधनों को बढ़ाने हेतु बाजार साम्यता तक नहीं पहुंच पाता है तथा किसानों को संस्थागत स्रोतों अथवा गैर-संस्थागत स्रोतों जैसे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। निजी स्रोतों से ऋण लेना आम बात है, परंतु प्राय: यह शोषण करने वाला है, बहुत ऊंचे दरों पर उपलब्ध है तथा ऐसे स्रोतों से ऋण लेने वाले प्राय: ऋण के क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा साहूकारों तथा अन्य निजी स्रोतों पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए कृषि में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए 1970 के बाद कई कार्य किए गए। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, कृषि के संस्थागत ऋण के प्रवाह में असाधारण बढ़ोतरी हुई है।

संस्थागत ऋण आपूर्ति में बढ़ोतरी के बावजूद, किसान परिवार साहूकारों तथा अन्य-गैर संस्थागत एजेंसियों के चंगुल से अपने आपको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यह संस्थागत

वित्तीय प्रणाली से अधिक प्रतिशत में छोटे तथा सीमांत किसानों के वित्तीय वर्जन को रोकने के लिए उपाय करने की मांग करता है। वित्तीय संस्थान के साथ अन्य गंभीर समस्या है कि कृषि ऋण का प्रवाह राज्यों तथा क्षेत्रों में एक समान नहीं है। महिला किसानों की ऐसे ऋण तक पहुंच नहीं है । कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के परिपेक्ष्य में विद्वानों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इस कमी को पूरा करने की मांग की है । यहां तक कि राज्यों में भी विकसित क्षेत्रों, वास्तविक अवसंरचना तक व्यापक पहुंच वाले क्षेत्र, अथवा विकासाधीन जिलों अथवा क्षेत्रों की तुलना में शहरी केन्द्रों के समीप क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में अंतर है।

संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए अभिनव उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में व्यापक उपायों की आवश्यकता है। जटिल कागजाती प्रक्रिया तथा ऋण लेने में उच्च अंतरण लागत का अनिवार्य रूप से समाधान किए जाने की आवश्यकता है। देश में सभी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने तथा समय-समय पर इसकी सीमा बढ़ाने की बहुत अधिक अपेक्षा है। सूदखोरों पर कुछ नियंत्रण तथा नियम होने चाहिए तथा साहूकारों तथा अन्य निजी स्रोतों से कृषि ऋण हेतु व्यापक मानक तथा शर्तों को अस्तित्व में लाना चाहिए।

समिति सुझाव देती है कि प्रत्येक राज्य के लिए संस्थागत ऋण की आपूर्ति हेतु कुछ न्यूनतम सीमा बनाए रखने की आवश्यकता है। यह सिफारिश करती है कि प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष लघु अवधिक ऋण के रूप में कृषि पैदावार के कम से कम 25 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति की जानी चाहिए। यह संख्या में भुगतान किए गए लागत मूल्य के प्रतिशत के लिए संगत है।

मंडी

कृषि मंडी उत्पादकों द्वारा प्राप्त मूल्यों तथा कृषि उत्पादों, विखंडित तथा दीर्घ विपणन चेनल, कमजोर अवसंरचना तथा नीति विकारों हेतु उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए गए मूल्यों के बीच अकुशलता, असंगति का सामना करता है। यह भी पाया गया है कि उत्पादन तथा विपणन में मिलाए गए कुल मूल्य में फसलोपरांत घटक में मूल्य वर्धित अंश बढ़ रहा है तथा इससे उत्पादन कम हो रहा है। कुछ मामलों में विपणन में मूल्य वर्धन उत्पादन में मूल्य वर्धन से अधिक है। फार्म का आकार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। विपणन यंत्रीकरण को विकसित एवं सुदृढ़ कर विपणन में मूल्य वर्धित अंश प्राप्त कर किसानों को समर्थ कर कृषि उत्पाद से आय को बढ़ाया जा सकता है जिसमें उत्पादकों को सहभागी के रूप में शामिल किया जाए। ऐसे

उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा कृषि मंडी में प्रभावी शर्तों को दूर करने के लिए अनिवार्य सुधारों की आवश्यकता है।

उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं हेतु सर्वोत्तम विपणन माडल उनके लिए है जहां, उत्पादक उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करते हैं चाहे वे व्यक्तिगत हो अथवा किसी तरह का कोई संगठन हो। ऐसे मॉडल को कुछ राज्यों में जैसे कि पंजाब तथा हरियाणा में अपनी मंडी, आंध्र प्रदेश में रायल बाजार तथा तमिलनाडु में उजावर सन्धाई के रूप में विकसित किया गया है। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, किसानों को चयनित दिन अथवा समय पर विचौलियों के बिना शहरों में उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर उत्पाद भेजने की अनुमति है। इन विपणन व्यवस्था के प्रचालन का स्तर काफी कम है, क्योंकि केवल बड़े शहरों के निकट रहने वाले किसान विपणन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार का हॉपकॉम्स अनुभव कर्नाटक में है । ऐसे अभिनव विपणन को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

कृषि उत्पादों की मांग पद्धति उपभोक्ता तथा उद्योग दोनों स्तर पर प्रसंस्कृत उत्पादों, गुणवत्ता उत्पाद तथा विशिष्टताओं के प्रति धीरे-धीरे बदल रही है। यह बदलाव परंपरागत विपणन चेनल की अपेक्षा समेकित आपूर्ति श्रृंखला, खुली मंडी की अपेक्षा आश्वस्त मंडी तथा जेनेरिक की अपेक्षा विशिष्ट उत्पाद का पक्ष लेती है। ऐसी आपूर्ति श्रृंखला विचौलियों के लाभांश को कम करने के लिए बहुत अधिक संभावना भी प्रदान करती है। एक बेहतर कार्य करने वाली आपूर्ति श्रृंखला किसानों को प्रसंस्करण फर्म तथा उपभोक्ताओं को अधिक निकटता से जोड़कर विपणन की लागत को कम कर सकता है तथा मात्रा, गुणवत्ता, किस्म तथा खाद्य सुरक्षा हेतु बदलते हुए उपभोक्ता वरीयताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन की निगरानी करता है। आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला में प्राय: निजी मानक तथा उनके प्रवर्तन भी शामिल होते हैं जो कुशलता बढ़ाकर तथा अंतरण लागत कम कर कई क्षेत्रों अथवा देशों में आपूर्तिकर्ता हेतु उत्पाद आवश्यकताओं को मानकीकृत कर समन्वय आपूर्ति श्रृंखला में सहायता करती है। आपूर्ति श्रृंखला की अवधारणा उन लघु धारकों के लिए अधिक लाभदायक है, जिनकी भारत की कृषि में प्रधानता है। लघु उत्पादों को एकत्र करने "समाकलक" संस्थान को बढ़ावा देने का तथा उत्पादकों की तरफ से अथवा अपने आप से मंडी में विक्रय का भी सुझाव दिया गया है।

तकनीकी सहायता के साथ सीधी खरीद जैसे कुछ प्रयोगों से किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ है। यह दर्शाते हैं कि विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत कृषि उत्पादों के लिए उत्पादक संस्था,

सहकारी विपणन समितियों का सहयोग किसानों के लिए मददगार हो सकता है। यह वर्तमान कृषि विपणन नीतियों में विस्तृत पुनरीक्षण की आवश्यकता है जो उत्पादकों को उपभोक्ताओं के करीब ला सके।

भारतीय कृषि को व्यापकता तथा विविधता प्रदान करने के लिए देश में एपीएमसी यंत्रीकरण, नए मॉडल तथा कुशलता प्रदान करने के लिए व्यवस्थित खुदरा सहित सहकारी दुग्ध विपणन जैसे सफल प्रयोगों को बढ़ाने तथा कृषि विपणन के प्रतिस्पर्द्धात्मक तथा आधुनिकीकरण सहित बहु दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सभी राज्यों को विशेष रूप में विपणन में उत्पादकों की मोलभाव क्षमता को सुधारने के लिए, उत्पादक संस्था उत्पादक कंपनियों, सहकारी-विपणन समितियों को बढ़ावा देने तथा विपणन में मूल्यवर्धन में उत्पादकों का अंश बढ़ाने की आवश्यकता है जो कि बढ़ता जा रहा है। आधुनिक एपीएमसी अधिनियम में कृषि विपणन के सुधारों की आवश्यकता का प्रस्ताव है। राज्यों को विशेष समूह के हित सेवा के लिए इसे कम किए बिना प्रतिस्पर्द्धा के सही ध्येय में मॉडल अधिनियम कार्यान्वित करना चाहिए । यह सीधे विपणन के जिस मार्ग, संविदा कृषि के माध्यम से वर्टिकल सहयोजन, उत्पादों की बिक्री के लिए उत्पादकों को वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक पर्यावरण सृजित करने के लिए सुनिश्चित मार्ग प्रशस्त करेगा जिस पर वर्तमान में कृषि उत्पाद मण्डी समिति का एकाधिकार है ।

जबकि कृषि विपणन में निजी क्षेत्रों की बढ़ी हुई भागीदारिता वांछित हैं देश को उत्पादकों जैसे सहकारी समितियों उत्पादक कम्पनियों और उत्पादक संघों की भागीदारी पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारिता और विपणन मॉडलो की बहुत अधिक आवश्यकता है । कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र और खाद्य विपणन उन्नत दक्षता के लिए निजी क्षेत्रों की आवश्यकता के रूप में प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । मण्डी कार्यों के माध्यम से मूल्य स्थिरता बनाए रखने के बड़े स्तर पर सामाजिक लक्ष्य सेवा के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है । निजी क्षेत्र को मूल्य स्थिरता में लाभ नहीं है, तो इससे यह लाभ प्राप्त करता है। यह बात पिछले छह वर्षों के वैश्विक अनुभव से मजबूत हुई है कि कभी भारत जैसे देश में आपूर्ति की कमी की स्थिति में स्टेपल खाद्य में सार्वजानिक क्षेत्र की मजबूत स्थिति के कारण मूल्य अस्थिरता से मंडी संरक्षण में सफल हुआ है। जब कि बहुत से विकास शील देश खाद्य स्टेपल्स में बिना सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति मूल्य अस्थिरता गंभीरता से जूझ रहे हैं ।

अन्य कोई संबंधित मामले

आधुनिक और प्रगतिशील कृषि को आधुनिक आदानों जैसे गुणवत्ता प्रद बीज, उर्वरक, कृषि रसायनों और कार्यकुशल कृषि मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है । यदि किसानों को यह उचित मूल्य पर, सही समय पर और सही स्थान पर सही गुणवत्ता का हो तो किसान इन आदानों का उपयोग करना चाहेंगे । सब्सिडी को छोडकर आदान मूल्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है| उत्पादन बढाने और विकास करने के लिए आधुनिक आदानों के उपयोग बढाने के लिए फार्म आदानों की आपूर्ति के लिए सुनिश्चित प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण के लिए यह आवश्यक है ।

कृषि में बीज प्रमुख आदान है । पिछले कुछ वर्षों तक सार्वजनिक क्षेत्र गुणवत्ता प्रद बीज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था । गुणवत्ता बीजों की मांग में वृद्धि के साथ और बीज उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि के कारण मूल्य महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है । बीज के लिए कुछ निजी कम्पनियों द्वारा असामान्यत: उच्च मूल्य लिए जाने की रिपोर्ट है । मोलक्यूलर जीव विज्ञान, जो पौध और पशुओं में जैनेटिक परीक्षण के लिए नया क्षेत्र खुला है, के वाणिज्यीकरण के कारण इस प्रकार की बीज के असामान्य मूल्य की घटना में वृद्धि हो रही है। यह रूझान न केवल बीज के उत्पादन में बल्कि अन्य आदानों जैसे शाकनाशी, जीवनाशी, फंगीनाशी उर्वरकों में भी दिखाई देता है। यह हमारे बहुत से विशेषताओं और उत्पादों पर एकाधिकार नियंत्रण के साथ उद्योगों के प्रकारों में बढ़ रहा है । इस प्रकार आदान मूल्यों पर तानाशाही रोकने के लिए एक या कुछ फर्मो की मण्डी अधिकार जॉचने के लिए एक आदान मूल्यों पर विनियामक प्राधिकरण की आवश्यकता है । उर्वरकों की मूल्य निर्धारण में भी बहुत से सन्देह है । सभी ऐसे मामलों के साथ सहयोग के लिए देश में एक फार्म आदानों से संबंधित मामलों के साथ सहयोग के लिए पर्याप्त अधिकारों के साथ कृषि आदान प्रतिस्पर्धा एवं विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता है । तथापि डीईएस का ऐसा मानना है की बाजार प्रभावी अर्थव्यवस्था में आदान मूल्यों पर बाजारी ताकतों का असर होता है इसलिए इन आदानों पर किसी विनिमायक प्राधिकरण का प्रभाव नहीं हो सकता | ऐसे कई

दूसरे विनिमायक प्राधिकरण क्रियाशील हैं जैसे भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग जो प्रतिस्पर्धा के मुद्दों को देखता है ।

मिलावटी आदानों की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है घटिया आदानों (बीजों, उर्वरक और रसायनों) की आपूर्ति के रिपोर्टों के रूप में देश के लगभग सभी भागों से दिन प्रतिदिन आ रही है । मिलावटी आदानों (बीज, ऊर्वरक और रसायन) का भारत के हर क्षेत्र में गतिमान है | मिलावटी आगत न केवल उन पर किये गये ख़र्च का नुकसान करते हैं अपितु आजीविका और आय के अवसर के नुकसान के साथ पूरे निवेश की प्राप्तियों के सन्दर्भ में भी हानिकारक होते हैं | गुणवत्ता जांच पद्धति को मजबूत बनाने के लिए आदान उध्योग में प्रतिस्पर्धा बढाने की आवश्यकता है |

अनुशंसाएं

प्रतिदर्श (नमूना) कार्य प्रणाली संबंधी मामले:

1. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित मुख्य फसलों की खेती की लागत के लिए व्यापक योजना के तहत प्रत्येक चुनी हुई तहसील/ब्लाक में से, वर्तमान में एक नमूना गांव का चुनाव किया जाता है । समिति यह सुझाव देती है कि नमूना गांव की वृहद कवरेज के लिए प्रत्येक चुनी हुई तहसील/ब्लाक से एक गांव के स्थान पर दो गांव का चुनाव किया जाना चाहिए । इसके लिए नमूना माप बढ़ने के अनुरूप अधिक संसाधन और श्रम शक्ति की अवश्यकता होगी जिससे कि किसानों से लागत आंकड़ों को प्राप्त करने की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

2. संचालनात्मक जोतें वर्तमान 5 आकार वर्गों के वर्गीकरण के स्थान पर तीन आकार वर्गों अर्थात् 1 है0, 1-2 है0 या 2 है0 से अधिक में वर्गीकृत होनी चाहिए और प्रत्येक आकार वर्ग से चुने हुए परिवारों की संख्या क्रमश: 3, 2 और 1 होनी चाहिए अर्थात् प्रत्येक गांव से 6 इकाईयां ।

3 (क) समिति द्वारा नमूना चयन के वर्तमान तंत्र में कमियां देखी गईं, जहां कुछ गौण फसलों के लिए चुना गया नमूना आकार बहुत छोटा होता है । समिति ने महसूस किया कि गौण फसलों के तहत क्षेत्र के लिए संभावना अनुपात से नमूना चुनाव कर समस्या पर काबू पाया जा सकता है । इस पर समिति ने तहसील और ब्लॉक का चुनाव करते वक्त प्रत्येक जोन, एक सामान्य (मुख्य फसलों के लिए) स्तर और एक अन्य गौण फसल स्तर के रूप में, के तहत उप स्तर की शुरूआत द्वारा मौजूदा नमूना डिजायन में संशोधन का सुझाव दिया है और आगे चुनी हुई तहसील में गांव का चुनाव करते समय बढ़ाया जा सकता है।

(ख) राज्य स्तर पर अनाज, दलहन और तिलहन के लिए इस समूह के तहत केवल उन्हीं फसलों का चुनाव किया जा सकता है ताकि वे क्रमश: इन्हीं समूहों के तहत कुल क्षेत्र का कम से कम 90% क्षेत्र कवर कर सकें। पटसन, नारियल और गन्ने के लिए मुख्य उत्पादक राज्य इस तरीके से चुने जाएं कि अखिल भारतीय स्तर पर कम से कम 90% क्षेत्र कवर हो । इससे नमूने में गौण फसल उत्पादक प्रचालनात्मक जोतों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के मौके बढ़ सकते हैं । यह नमूना कार्य प्रणाली दृष्टिकोण अंतिम अपनाने से पहले पायलट आधार पर आजमाया जा सकता है ।

4. संग्रहित प्राथमिक डाटा की गुणवत्ता और उचित क्षेत्र देखरेख में सुधार के लिए क्षेत्र पर्यवेक्षक और क्षेत्र अन्वेषकों/फील्डमैन का अनुपात वर्तमान 1:10 के स्थान पर 1:6 होना चाहिए| हालांकि नमूना माप बढने की वजह से और डाटा की अच्छी तरह से जांच करने के लिए अधिक क्षेत्र पर्यवेक्षकों की आवश्यकता होगी जिसके लिए जरूरी प्रावधान करने चाहिए |

5. तीन साल की ब्लाक अवधि के लिए चुनिंदा किसान/परिवारों से सूचना संग्रह की वर्तमान प्रणाली अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए । सीएस के तहत सृजित लागत अनुमान प्रदान करने का समय कम करने के लिए एक अद्यतन साफ्टवेयर की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है ।

6. अकेले उत्पादन में निरंतर समय लगाना और सामान्य श्रमिक की मजदूरी दर से इसका मूल्यांकन करना किसान के समय का बहुत कम मूल्यांकन है, जबकि यह अनुभव किया गया है कि किसानों को खेती के काम में विशेषज्ञ की तरह उपचारित किया जाना चाहिए | समिति ने सुझाव दिया है कि परिवार का प्रधान जो खेती में व्यस्त है, उसकी मजदूरी का आकलन कौशल मजदूरी दरों के आधार पर होना चाहिए | इसके अतिरिक्त किसानों के खतरा लाभ तथा प्रबंधकीय प्रभारों को महत्व देते हुए सी 2 लागत को 10 प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए | तथापि डीईएस इससे सहमत नहीं था और उसने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया कि पारिवारिक श्रम सहित पेड-आउट लागत (ए2+एफएल) का 10 प्रतिशत को ए2+एफएल लागत में जोड़ा जाना चाहिए ताकि किसानों का प्रबंधकीय प्रभार वहन हो सके ।

अनुशंसाएं

7. कार्यशील पूंजी पर ब्याज का आकलन पूरी फसल अवधि न कि आधी पर किया जाना चाहिए और नमूना किसानों द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किया गया ब्याज होना चाहिए।

8. भूमि किराया मूल्य नमूना गांव में प्रबल वास्तविक दरों के आधार पर और उक्त पर बिना किसी सीमा निर्धारण में विशेष रूप से नमूना किसानों के साथ होना चाहिए ।

9. पशु श्रम शुल्क बैल जोड़ी द्वारा कार्य के केवल धंटों के अनुसार नहीं होना चाहिए बल्कि केवल नमूना किसानों द्वारा सूचना अनुसार काम किए गए फसल क्षेत्र के अनुपात पूरे वर्ष की लागत होना चाहिए तथापि डी.ई.एस ने यह बताया कि लागत इसी तरह निकाली जाती है फिर भी अगर इस पद्यति में कोई विसंगति है तो उसे त्यागना चाहिए|

10. फसलोपरांत लागत जैसे सफाई, सुखाई, पैकेजिंग, किसानों द्वारा उत्पाद का बाजार में विपणन और परिवहन में किया गया व्यय को सीओसी का हिस्सा होना चाहिए । यह सिफारिश भी की गई है कि खेती की सी2 लागत पहुँचने पर आने के लिए उचित जोखिम मार्जिन को जोड़ा जाना चाहिए । तथापि इस मुद्दे पर डीईएस ने रेखांकित किया है कि सीओसी एक्स फार्म लागत है और इसकी रू0/है0 में गणना की जाती है जबकि विपणन और परिवहन लागत फसलोपरांत लागत है और रू0/क्वि. में गणना की जाती है इसलिए ऐसी लागतें सीओसी का हिस्सा नहीं हो सकती तथापि सीएसीपी को लागत अनुमान भेजते समय इन लागतों को अलग से इंकित किया जाना चाहिए और सीएसीपी एमएसपी के विचार के समय इन लागतों को सी2 लागत में जोड़ें |

11. समिति ने पाया है कि जिस वर्ष के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है उसके लिए नियत लागत के विविध मदों का प्रक्षेपण नहीं किया जाता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि नियत पूंजी पर ब्याज और मूल्यह्रास को निर्माण सामग्री में मुद्रास्फीति की दर से बढ़ा करके प्रक्षेपित किया जाए। कार्यशील पूंजी पर ब्याज को संयुक्त परिवर्तनीय आदान सूचकांक के अनुसरण बढ़ा कर के प्रक्षेपित किया जाना चाहिए । भूमि किराए का प्रक्षेपण कृषि जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए जो भूमि किराए में प्रमुख परिवर्तन निर्धारक है । तथापि इस मुद्दे पर सीएसीपी ने व्यक्त किया है कि नियत लागत में नियत पूंजी पर ब्याज और स्वामित्व भूमि का किराया मूल्य शामिल होता है । नियत पूंजी पर मूल्यह्रास और कार्यशील पूंजी

पर ब्याज (जो नियत लागत का भाग नहीं है) का प्रक्षेपण अलग से होता है । इसलिए स्वामित्व भूमि का किराया मूल्य और नियत पूंजी पर ब्याज को नियत लागत के प्रक्षेपण के लिए विचार करना पड़ेगा । इसलिए समिति ने यह सुझाव दिया है कि सीएसीपी नियत लागत के प्रक्षेपण के लिए अलग से ऐसी पद्यति जांच सकती है जो की वास्तविकता के नजदीक है |

12. राष्ट्रीय स्तर पर लागत का औसत लेने के लिए निर्देशित सिद्धांत किसानों की क्षमता और अधिकतम किसानों के कवरेज के बीच संतुलन बैठाना चाहिए । क्षमता मानदंड का औसत लेने के लिए एक समान नियम है जो गणितीय साधनों और किसानों के अधिकतम औसत यानि 100 प्रतिशत का प्रयोग करते हैं । इससे यह परिणाम निकलेगा कि किसानों के 75% [(50+100/2)] की बल्क लाईन लागत सी2 के पुनर्प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है । वर्तमान में डी.ई.एस स्थापित आकलन पद्यति में सभी फसलों का राज्यवार लागत अनुमान आंकलित करती है | तथापि अधिकतम किसानों को कवरेज के लिए डी.ई.एस समिति द्वारा सुझाये गये बल्क लाइन लागत का विश्लेषण कर सकता है |

सीएसीपी का अधिदेश:

13. सीएसीपी कृषकों और कृषि क्षेत्र की चिंताओं को बताने वाला और किसानों के हितों की रक्षा करने वाला उचित निकाय है । समिति संस्तुत करती है कि सीएसीपी की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए और इसका नाम 'कृषि लागत, मूल्य और नीति आयोग' होना चाहिए। सीएसीपी को व्यापक योजना में संकलित डाटा के आधार पर विभिन्न फसल संघटनों और किसानों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए फार्म आय पर सूचना देनी चाहिए और फार्म आय व लाभदायक मूल्यों से संबंधित सिफारिश करनी चाहिए । खाद्य, कृषि और किसानों पर विभिन्न नीतियों के विश्लेषण के लिए उचित स्टाफ के साथ सीएसीपी में चार व्यवसायिक विशेषज्ञ होने चाहिए। आयोग को कृषि व्यवस्था, खाद्य कीमतों और उभरती स्थिति में नीति सिफारिशों की सूची के साथ किसानो की दशा पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए| सीएसीपी की मूल्य नीति की रिपोर्ट की तरह मंत्रीमंडल के समक्ष इसको कार्यान्वित करने के लिए रखा जाना चाहिए| तथापि डी०इ०एस० का यह मानना है कि नीतियों का निर्धारण सरकार का अधिदेश है और इसे आयोग को नहीं दिया जा सकता और सुझाव है कि सीएसीपी द्वारा नीति निवेशों पर मूल्य नीतियों पर

दी गई रिपोर्टों जिनमे मूल्यगत और गैर मूल्यगत दोनों सिफ़ारिशे शामिल होती हैं, को सरकार द्वारा यथोचित मान देना चाहिए |

14. सीएसीपी को संस्तुति और घोषित एमएसपी को कानूनी मान्यता देते हुए यह देखने के लिए कि किसानों को एमएसपी से नीचे का मूल्य न दिया जा रहा हो, सभी राज्यों में सभी फसलों के लिए सीजन में फसलोपरांत मूल्य की निगरानी करनी चाहिए। यदि मूल्य वैधानिक एमएसपी से नीचे चले जाए, सीएसीपी को स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को तत्काल सिफारिश करनी चाहिए।

15. यह स्वाभाविक है कि सभी जगह खरीद के माध्यम से मूल्य गारंटी सुनिश्चित नहीं की जा सकती, अत: सभी फसलों की मूल्य सुनिश्चितता के लिए कमी मूल्य भुगतान अथवा मूल्य सीमा जैसे तंत्र शुरू किए जाने चाहिए । हालांकि डी०इ०एस० ने यह अंकित किया है कि मूल्य कमी भुगतान तंत्र भारत में ठीक नहीं है क्योंकि यह उन देशों में प्रचलित है जहां दो या तीन फ़सलें कवर की जाती हैं | मूल्य कमी तंत्र को भारत नहीं अपना सकता जहां एम०एस०पी० के अंतर्गत 23 फसलें आती है | जहां भी बाजार भाव एम०एस०पी० से नीचे जायें वहां सरकारी खरीद को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे किसानों को एम०एस०पी० सुनिश्चित हो सके। डी०इ०एस० के अनुसार जहां भी ऐसी जरूरत हो वहां सरकारी खरीद करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए |

16. सीएसीपी को कृषि एवं किसानों को प्रभावित करने वाली विभिन्न नीतियों के साथ-साथ मूल्य और फार्म आय की वार्षिक समीक्षा प्रकाशित करनी चाहिए जिन्हें संसद के बजट सत्र में रखा जाना चाहिए। तथापि डी०इ०एस० का यह मानना है कि सीएसीपी की रिपोर्ट को संसद में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है| सीएसीपी से संबंधित विविध मामलों पर विविध सिफ़ारिशें कृषि की संसदीय स्थायी समिति, मांग एवं अनुदान संसदीय समिति और अन्य इस तरह की समितियों में विस्तार से विचार विमर्श करती है|

17. व्यापार उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ व्यापार नीति के उपकरण से फार्म मूल्य बेहद प्रभावित होना शुरू हो गए हैं। प्रशुल्क (टैरिफ) व निर्यात और आयात के निर्णय उपभोक्ताओं के हितों पर आधारित होते हैं । समिति यह महसूस करती है कि सीएसीपी

को इसमें शामिल किया जाना चाहिए तथा सभी व्यापार नीति निर्णयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए ।

अन्य मामले:

18. समिति महसूस करती है कि प्रशुल्क (टैरिफ), कर, ऋण और बाजार की संरचना का उत्पादन लागत और उत्पाद मूल्यों पर अधिक प्रभाव होता है और फलस्वरूप फार्म आय भी प्रभावित होती है | इसलिए मूल्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इन तथ्यों को मूल्यों के तथ्यों के साथ विचार करने चाहिए |

19. देश में बड़े पैमाने पर उत्पादित खाद्य तेलों जैसी खाद्य वस्तुओं के आयात पर अधिक और लगातार निर्भरता कम होनी चाहिए । समिति का सुझाव है कि कच्चे तेल के साथ-साथ परिष्कृत खाद्य तेलों पर प्रशुल्क (टैरिफ) प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए तिलहन क्षेत्र को स्वीकृती देने के लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए । समिति बल देती है कि सीएसीपी से प्रशुल्क(टैरिफ) और व्यापर नीति पर परामर्श लेना चाहिए तथा उसकी सिफारिशों को मान देना चाहिए ।

20. उद्योगों से विभिन्न, संसाधनों को बढाने के लिए बाजारी शेयर में कृषि क्षेत्र की पहुँच नहीं है और किसानों को परंपरागत या गैर परंपरागत स्त्रोतों से जैसे साहूकार जो कि अक्सर मजबूरी का फायदा उठाने वाले होते है से ऋण लेना पड़ता है | समिति यह सुझाती है कि किसानों के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित निश्चित सीमा के साथ संस्थागत ऋण की आपूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य को एक न्यूनतम सीमा बनाए रखने की आवश्यकता है| यह सुझाया जाता है कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष लघु अवधि ऋण के रूप में कृषि उपज के मूल्यों की कम से कम 25 प्रतिशत आपूर्ति की जानी चाहिए। यह आंकड़ा फसल और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में विभिन्न आदानों (श्रम के अलावा) के शेयर के अनुरूप है ।

21. कृषि उत्पाद के लिए बाजार अन्य विकासों के साथ विकसित नहीं हो रहें हैं । उपभोक्ता और उद्योग स्तर पर कृषि जिंसों की मांग पद्धति प्रसंस्कृत उत्पादों, गुणवत्ता उत्पाद और विशिष्ट लक्षणों की ओर तेजी से परिवर्तित हो रही है । इसके मौजूदा कृषि विपणन नीतियों और कार्यान्वयन परिवर्तनों की पूर्णत: समीक्षा होनी चाहिए जिससे उत्पादक

उपभोक्ता के नजदीक आयेंगे और उत्पादकों के लिए भी खुदरा मूल्य का बड़ा भाग प्राप्त हो सकेगा।

22. भारतीय कृषि की व्यापकता और बहुरूपता को ध्यान में रखते हुए देश को एपीएमसी तंत्र, नये मॉडलों सहित बहु-आयामी दृष्टिकोणों और कृषि विपणन के लिए कार्य क्षमता, प्रतिस्पर्धा और आधुनिकीकरण प्रदान करने के लिए संगठित खुदरा बाजार के साथ सहकारी दुग्ध विपणन जैसे सफल अनुभवों को अपस्केल करने की अनुभवों को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है । सभी राज्यों में विशेष रूप से विपणन में उत्पादकों की मोल भाव क्षमता में सुधार करने के लिए उत्पादक संघों, उत्पादक कम्पनियों, सहकारी विपणन समितियों के प्रोन्नयन और विपणन में मूल्य संवर्धन में उत्पादकों के शेयर को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

23. उत्पादन में तेजी और वृद्धि बनाये रखने के लिए निश्चित आदानों के उपयोग के प्रोन्नयन के लिए फार्म आदान की आपूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धी वातावरण सुनिश्चित करना आवश्यक है. बीज और अन्य आदानों का मूल्य और गुणवत्ता विवादास्पद मुद्दे बन गये हैं। फार्म आदानों से संबंधित मुद्दों जैसे मूल्य उपलब्धता और गुणवत्ता के निपटान के लिए देश में उचित शक्तियों के साथ "फार्म आदान प्रतिस्पर्धा और विनियमन प्राधिकरण" की स्थापना की आवश्यकता है। तथापि डीईएस का ऐसा मानना है की बाजार प्रभावी अर्थव्यवस्था में आदान मूल्यों पर बाजारी ताकतों का असर होता है इसलिए इन आदानों पर किसी विनिमायक प्राधिकरण का प्रभाव नहीं हो सकता | ऐसे कई दूसरे विनिमायक प्राधिकरण क्रियाशील हैं जैसे भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग जो प्रतिस्पर्धा के मुद्दे को देखता है ।

*****

Report of the Committee to Examine Methodological Issues in Fixing Minimum Support Prices

(53)

CONTENTS

Sections		Page No.
	Acknowledgements	1
1	Introduction	2-4
2	Mandate of CACP	5-9
3	Cost concepts and imputation	10-17
4	Tariff, taxes, credit and market	18-22
5	Any other related matter	23-24
6	Recommendations	25-29
Annexures		
I	Constitution of the Committee and Terms of Reference (ToR)	A-1 to A-3
II	Minutes of Meetings	A-4 to A-14

Acknowledgements

The Committee records its sincere thanks to Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India for providing the opportunity to the Committee to "Examine Methodological Issues in Fixing Minimum Support Prices, Terms of Reference of CACP and other Related Aspects of the System".

The Committee thanks all the members of the Committee for their active participation in the deliberation and for making valuable suggestions for preparation of the report. The Committee wishes to place on record its appreciation for the valuable input received from Department of Agriculture and Cooperation and Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India. The material supplied by these departments was of immense value in deliberating the subject matter in depth.

The Committee expresses its gratitude to Shri Ashish Bahuguna, Ex-Secretary, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture for taking keen interest in preparation of this report. The Committee would like to put on record its appreciation and thanks to Sh. S.R. Joshi, Member Secretary of the Committee and Adviser (Cost), CACP for excellent co-ordination among the members of the Committee and for organizing various meetings.

The committee appreciates and thanks the team led by the Member Secretary for the initiative and efforts made for bringing out the Hindi Version of the Minutes of the Meetings and the Report of the committee.

The Committee is also thankful to the officers of Cost Division of CACP and E.A. Division of the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, for organizing the meetings, and for arranging the logistics.

30
March, 2015

(Prof. Ramesh Chand)
Chairman of the Committee

Introduction

Agricultural production, marketing and trade have undergone significant changes in the last three decades. Two episodes that have profound impact on almost all aspects of agriculture are (a) economic liberalization that started in the country since 1991 and (b) setting up of World Trade Organization (WTO) in the year 1995 and bringing agriculture under General Agreement on Trade and Tariffs. However, agriculture has changed because of many other factors as well, most of which have some implications for price policy, farmers' livelihood and income.

Production patterns have moved towards cash crops and many crops which were earlier for subsistence or for meeting family food requirement are now grown largely based on cash considerations. Proportion of marketed surplus in production has risen for almost all crops. Production has become highly commercialized with increase in use of purchased inputs, replacement of family labour by hired labour, substitution of labour with capital and machinery and monetization of rural economy. Adoption of improved technology has necessitated use of market purchased seeds often at a high cost. Price shocks have become frequent and severe. The pressure to meet family expenditure to meet necessities of modern life has been forcing farmers to embrace risky ventures by using borrowed funds. Risk unleashed by market forces and price crash in many cases are leading to agrarian distress and sad situations like farmers' suicides.

There is a lot of disenchantment among farmers with the existing system of procurement mechanism based on minimum support prices followed in the country. Moreover, except for paddy, wheat, cotton, sugarcane, jute and copra; no effective procurement mechanism exists to ensure that prices received by farmers do not fall below minimum support prices (MSP). Even in the case of paddy, wheat and cotton; the MSP is effective only in some states where public procurement system is in place. In other places, actual price received by farmers turn lower than MSP in several instances. Similarly, farm harvest prices of other cereals, pulses and oilseeds in several markets often remain lower than their MSP.

Questions have also been raised about the methodology used by the Commission for Agricultural Cost and Prices (CACP) to arrive at MSP for various crops. The common perception is that cost of cultivation per unit of output is the sole criterion used by CACP to arrive at its recommendation about MSP. This is the reason that various farmers' organizations contest methodology, accuracy and reliability of the data on cost of cultivation/production as collected by the Directorate of Economic and Statistics, of Ministry of Agriculture. Suggestions have been made by high level committees like National Commission on Farmers, to fix MSP at least 50% more than the weighted average cost of production. There are considerable variations in the cost across states, and a particular level of MSP may be 50% higher than the average cost of production in some states and lower in some other states, given that a national weighted average is used to arrive at average cost of production.

There are various important factors other than MSP which also strongly affect farm harvest prices received by farmers. This is particularly true for those crops and farmers which are not directly benefited by MSP. These factors include tariffs, interest rate on non-institutional credit, input subsidies, taxation structure, infrastructure, market regulations, stage of market development and market competition. In many cases farmers can get better prices than MSP, if policy environment is favourable. Conversely, unfavourable policy environment can turn ruinous for the farmers. Despite this fact, most of the focus for getting better treatment for the farmers is on the prices. CACP is particularly saddled with this, partly due to its mandate and partly due to its historical legacy. Thus, it is pertinent to look at the role of CACP in the wake of effect of other policies on farm prices and in the wake of ongoing liberalization, privatization and globalization.

In this background a committee was constituted by the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India on 1st April, 2013 to examine (i) existing mandate of CACP, (ii) various aspects of fixation of MSP, and (iii) other policies affecting farmers and prices of farm produce . The specific terms of reference of the Committee were as under:

a) To examine the existing mandate of the Commission for Agricultural Costs and Prices and suggest whether – by way of a measure of response to the rapidly changing external environment arising in the wake of liberalization, privatization and globalization – there is need to reposition the Commission in terms of its mandate and remit.

b) To examine the existing cost concepts for the purpose of fixing minimum support prices and suggest various factors including cost of transportation, marketing, processing, storage etc. to determine MSP. Besides the Committee may also analyse the appropriateness of existing methods followed in imputing the value of (i) family labour; (ii) rental value of land; (iii) interest or capital; (iv) depreciation on fixed items such as tractors, bullocks etc. and recommend measures for improvement so as to make them more realistic.

c) To examine the existing structure of tariff, taxes, credit, market etc. and to suggest various measures to make it most competitive and remunerative to the farmers in the wake of trade liberalization and globalization and also to encourage agricultural growth.

d) To examine any other related and relevant matters that are important for improving the system.

Constitution of the Committee

The Committee constituted by the Government was chaired by Prof. Ramesh Chand, Director, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi, and it has members from academia, farmers' organizations, CACP, Ministry of Agriculture and state government representatives. The constitution of the committee with its specific Terms of Reference (TOR) is given in Annexure I.

Modus Operandi

The Committee held five meetings in which detailed discussions were undertaken on several issues encompassing the TOR. The members of the committee were benefited by the presentations made by officers/experts of Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation and CACP detailing the Comprehensive scheme for cost of cultivation of principal crops and methodology adopted for projecting cost estimates to arrive at the recommendations of MSP. The Minutes of various meetings are enclosed in Annexure II.

Mandate of CACP

The mandate of CACP is expressed in its Terms of Reference which have been periodically reviewed. The Commission was set up in year 1965 vide resolution of the then Ministry of Food and Agriculture, and it was named as Agricultural Prices Commission. According to the resolution the Commission was set up to evolve a balanced and integrated price structure and was mandated to advise on the price policy of 11 agricultural crops/group of crops. Subsequently, the Commission was renamed as Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), its present name, in year 1985. The current TOR for CACP notified in year 2009 are as under (CACP Discussion Paper 7, 2013):

1. To advise on the price policy of paddy/rice, wheat, jowar, bajra, maize, ragi, barley, gram, tur, moong, urad, sugarcane, groundnut, soybean seed, rapeseed &mustard, cotton, jute, tobacco, sesamum, nigerseed, lentil (masoor), safflower, copra and such other commodities as the Government may decide from time to time, with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall needs of the economy and with due regard to the interests of the producer and the consumer.

2. While recommending the price policy and the relative price structure, the Commission may keep in view the following:-
   i) The need to provide incentive to the producer for adopting improved technology and for developing a production pattern broadly in the light of national requirements.
   ii) The need to ensure rational utilization of land, water and other production resources.
   iii) The likely effect of the price policy on rest of the economy, particularly on the cost of living, level of wages, cost structure of agro-based products and the competitiveness of agriculture and agro-based commodities.

3. The Commission may also suggest such non-price measures related to credit policy, crop and income insurance and other sectors as would facilitate the achievements of the objectives set out in 1 above.

4 To recommend from time to time, in respect of different agricultural commodities, measures necessary to make the price policy effective.

5 To take into account the changes in terms of trade between agriculture and non – agricultural sectors.

6. To examine, where necessary, the prevailing methods and cost of marketing of agricultural commodities in different regions, suggest measures to reduce costs of marketing and recommend fair price margins for different stages of marketing.

7. To keep under review the developing price situation and to make appropriate recommendations, as and when necessary, within the framework of the overall price policy.

8. To undertake studies in respect of different crops as may be prescribed by Government from time to time.

9. To keep under review studies relating to the prices policy and arrangements for collection of information regarding agricultural prices and other related data and suggest improvements in the same, and to organize research studies in the field of price policy

10. To advise on any problems relating to agricultural prices and other production that may be referred to it by Government from time to time.

11. To effectively integrate the recommended non-price measures with price recommendations and to ensure competitive agriculture.

The above-mentioned TOR is quite comprehensive, which covers a large number of aspects. The general feeling of the committee is that these TOR require CACP to make its recommendations about MSP keeping in view the interest of producers, consumers and overall economy. The Commission holds detailed discussions with representatives of Farmers Organisations/Associations and also undertakes field visits to different states so as to discuss

various issues of current relevance to the farmers before formulating its Price Policy reports. While making price policy recommendations, the interest of the farmers occupy the commanding priority of CACP.

The committee notes that the existing TOR of CACP seeks to promote production, balanced growth, sustainability, crop parity and some other economic aspects, which are quite relevant and important. However, the TOR is completely silent about farmers' concerns related to viability of farming, profitability, adequacy of farm income, disparities between agriculture and non-agriculture income, modernization of farming, agricultural infrastructure, input prices, market development, and various other aspects affecting agriculture and agriculturists. All these aspect are important for sustaining interest in farming and for well being of farmers.

The TOR 4 requires CACP to recommend from time to time measures to make price policy effective. The Commission devotes a full chapter on demand-supply and efficacy of price policy which includes the comparison of WPI of crops with MSPs, procurement policy and its operation, market distortions in its various Price Policy Reports. In these reports, the commission has been recommending setting up of additional procurement centres, especially in the far flung areas to take care of the 'price assurance'. . However, these non price recommendations of the CACP hardly get attention of the government as the Commission is perceived as a body to make recommendation on the prices only. It is common knowledge that price support policy is effective only in some crops namely paddy/rice, wheat, cotton and sugarcane. Even in the case of paddy/rice and wheat, the MSP is not effective in all markets; it is effective only in some states, where public procurement is in place. In several markets in various states, prices received by farmers often rule below the MSP. This has been acknowledged in the documents of Planning Commission and even in the reports of CACP. This require concrete and effective mechanism to ensure that farmers receive at least that price for their produce which has been given to them as assurance in the form of MSP.

The CACP should suggest and recommend mechanisms to ensure that farmers are appropriately compensated for the loss of revenue realization on their marketed surplus when market prices in the harvest season rule lower than MSP. It is obvious that MSP cannot be implemented everywhere through system of procurement. Therefore, alternative mechanisms like Deficiency Price payment or Price Insurance should be put in place for price surety for all the crops for which MSP is declared. *However, DES pointed out that Deficiency Price Payment as a price guarantee is not appropriate for India as this is prevalent in the countries where only one or two crops are covered. Deficiency Pric e mechanism cannot be adopted for India where 23 crops are covered under MSP. Instead there is a need to strengthen the procurement to ensure MSP for the farmers whenever the market price falls below the MSP.*

According to DES, the procurement for ensuring MSP should be primary responsibility of the State Governments which may undertake procurement whenever required.

The committee feels that the CACP should monitor farm harvest prices in the marketing season for all important crops in all the states to oversee that farmers are not paid price below MSP. If that happens, CACP should make immediate recommendations to government to address the situation. The CACP should publish annual review of prices and various policies affecting agriculture and farmers, which should be placed in the Parliament in budget session. *However, DES is of the view that there is no need for placing the report of CACP in the Parliament. The various recommendations on various issues relating to CACP are discussed in detail in the Parliamentary Committee on Agriculture, Parliamentary Standing Committee on Demand and Grants and other such Committees.*

Some aspects which seriously impinge upon producers' interest are still not covered by the existing TOR. The most notable among these is trade policy covering export/import regulations and tariff. With the rising trade liberalization and globalization, instruments of trade policy have started affecting farm prices strongly. The CACP does not seem to be playing any role in relation to trade regulation on agricultural products. The tariffs, exports and imports decisions are generally taken based on interest of consumers and industry. Many a times, they cause kneejerk price shocks to producers. It has become almost routine to put various types of restrictions on agricultural exports, when domestic prices go high. However, imports are not strictly regulated in response to the requirements of producers and agricultural sector. Though CACP, in its price policy reports gives recommendations related to trade regulations on agricultural products however, the committee feels that CACP should be consulted in all such trade policy decisions.

The Industry and other sectors have strong professional bodies like FICCI, CII, ASSOCHAM, and PHDCCI to articulate their concerns and to lobby for policies in their favour. There is no such pan India or regional professional body equipped with professionals to articulate interest of agriculture sector and farmers. CACP is the appropriate body to articulate the concern of farmers and agriculture sector and to advance interest of farmers.

CACP is the appropriate body to articulate the concerns of farmers and agriculture sector and to advance interest of farmers. The Committee recommends that the role of CACP should be expanded and it should be renamed as **"Commission on Agricultural Costs, Prices and Policies"**. The CACP should also be equipped with professional experts at senior level with sufficient support staff to undertake analysis of various policies on food, agriculture and

farmers. The Commission should submit quarterly report on (i) state of agriculture, food, prices and (ii) state of farmers with list of policy recommendations to respond to the emerging situation. The quarterly report should be placed before the Cabinet, like CACP report on Price Policy, for considering its implementation. It is also recommended that CACP should be involved in pre-budget consultations. The Commission should recommend specific policies for improving the incomes of farmers in a focused manner. *However, DES is of the view that policy formulation is mandate of the Government and this cannot be assigned to the Commission and suggests that the various policy inputs provided by the CACP under various price policy reports submitted by the CACP are given due consideration by the Government which includes both price and non price recommendations.*

Cost Concepts and Imputation

The Commission formulates its recommendations in respect of the level of Minimum Support Prices and other non-price measures, by taking into account, apart from a comprehensive view of the entire structure of the economy of a particular commodity or group of commodities, the following factors:

i) Cost of production

ii) Changes in input prices

iii) Input-output price parity

iv) Trends in market prices

v) Demand and supply

vi) Inter-crop price parity

vii) Effect on industrial cost structure

viii) Effect on cost of living

ix) Effect on general price level

x) International price situation

xi) Parity between prices paid and prices received by the farmers

xii) Effect on issue prices and implications for subsidy.

The estimates of Cost of Cultivation/Cost of Production, an important input for forming the recommendation of MSP, are made available to the Commission through the Comprehensive Scheme for Studying the Cost of Cultivation of Principal Crops, operated by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India. These estimates take into account real factors of cultivation and include all actual expenses in cash and kind incurred by the farmer in cultivation, rent paid for leased in land, imputed value of family labour, interest value of owned capital assets

(excluding land), rental value of owned land (net of land revenue), depreciation on farm implements and buildings and other miscellaneous expenses.

The nomenclature and terminology of various cost concepts used for the purpose of fixing minimum support prices are as under:

Paid-out Costs

i. Hired labour (human, animal and machinery).

ii. Maintenance expenses on owned animals and machinery.

iii. Expenses on material inputs such as seed (home grown and purchased), fertilizer, manure (owned and purchased), pesticides, insecticides, weedicides and irrigation.

iv. Depreciation on implements and farm buildings (such as cattle sheds, machine sheds, storage sheds).

v. Land revenue and other taxes

vi. Miscellaneous expenses

vii. Rent paid for leased- in land.

Imputed Costs

i. Value of family labour,

ii. Rent of owned land; and

iii. Interest on owned fixed capital and working capital.

The following standard cost notations are used:

Cost A1: All actual expenses in cash and kind incurred in production by owner operator

Cost A2: Cost A1+ rent paid for leased-in-land

Cost B1: Cost A1 + interest on value of owned capital assets (excluding land)

Cost B2: Cost B1 + rental value of owned land (net of land revenue) and rent paid for leased-in-land

Cost C1: Cost B1+ imputed value of family labour

Cost C2: Cost B2 +imputed value of family labour

Cost C3: Cost C2 plus 10 per cent of cost C2 to account for managerial input of the farmer.

Generally, C2 cost is considered as one of the important factors while arriving at the recommendation for MSP. This is a comprehensive cost as far as production is concerned and it includes paid out cost and imputed value of inputs, services and resources contributed or owned by farm family like usage of family labour, use of farmer's own capital and use of own land for the crop production activity. Since the inputs contributed by family are not transacted with third party or in the market, their cost is arrived at indirectly through method of imputations. Thus, even when MSP recommended is exactly same as the cost C2, some return (income) will be accrued to the farmers in the form of imputed cost of family labour, interest on fixed capital and rental value of owned land which is not the part of paid-out cost incurred by the farmer in cash/kind.

Farmers have been raising the issue of proper valuation of their time, rental value of their land, interest on capital, depreciation etc. and seeking more realistic treatment of these items.

Imputation of Family Labour

The family labour cost is computed on the basis of actual market wage rate in the locality or statutory wage rate whichever is higher. This type of treatment does not recognize value of farmers' skills in terms of decision making, risk taking and his/her business acumen. Also, the time spent by farmer on planning, general care on a day-to-day basis, visits to arrange inputs and other resources for farm business, participation in farm related general activities is not counted. Several members of the Committee note that the innovations and skills of the farmers are not given due consideration while imputing their wage rates. Thus the committee feels that counting time spent by farmers in production alone and valuing it at the wage rate of ordinary labour is gross undervaluation of the farmer's time, whereas it is felt that farmers should be treated as expert in agricultural work. The committee suggests that head of the family engaged in farming should be valued at skilled wage rates. In addition, cost C2 should be raised by 10 percent to account for the risk premium and managerial charges of a farmer. *However, DES differed on this issue and alternatively suggested that 10 percent of the paid-out cost including family labour (A2+FL) should be added to cost A2+FL to account for the managerial charges of a farmer.*

Rental Value of Own Land

The land rent is estimated at present on the basis of prevailing rents in the village for identical type of land or as reported by the sample farmers – however, this is subject to the ceiling of fair rents given in the land legislation of the concerned state. The committee recommends that this should be calculated at the prevailing rent or as the actuals reported by the sample farmers, without any ceilings applied.

Interest on Owned Fixed Capital and Working capital

Interest on working capital is charged at the rate of 12.5 per cent per annum for half of the period of crop, and, the interest on present value of fixed asset is charged at the rate of 10%. These interest rates refer to interest charged by institutional sources. Farmers have to incur lot of cost in terms of time and paper work and other formalities to get loan from institutional sources. Thus, cost of borrowing is much higher than the interest cost. Some studies show that in some cases non interest cost is higher than the interest cost. Thus, it is pertinent to include in COC questionnaire information on cost of borrowing and consider it in cost of cultivation. Many a times farmers are not able to get loan from institutional sources or institutional loan is not adequate, and they borrow from non institutional sources and pay much higher interest rates. Since Cost of Cultivation questionnaire contains information on source of credit and interest paid thereon, it will be more realistic to use actual interest paid on institutional and non institutional borrowings by loanee sample farmers to impute value of interest on owned fixed capital and working capital.

It seems that charging interest on working capital for half of the crop season is based on perfect flow of resources matching use of input. This does not hold good in agriculture. The short term or crop loan are taken at the time of sowing of crops and repaid after the harvest. Thus, interest is paid for full life of crop season. It is, therefore, suggested that interest on working capital should be estimated for whole, not half, of the period of crop season, and on an actual basis as paid by sample farmers.

Processing, Transport and Marketing Cost

The cost of cultivation data presented in CACP reports and Cost of cultivation reports of DES does not include post harvest costs like cleaning, grading, drying, packaging, marketing and transport of produce to market, incurred by farmers, before sale realization. However, such costs are included in the Questionnaire of COC scheme. The Committee recommends that these costs should form part of COC. It is also recommended that appropriate risk margin should be added to arrive at C2 cost of cultivation. *However, on this issue DES outlined that COC is ex-farm costs and calculated in Rs/ha, whereas marketing & transport costs are post-harvest costs and calculated in Rs/Qtl. Therefore, such costs cannot be the part of COC.* Alternatively, It is suggested that all these costs should be indicated separately while forwarding costs estimates to CACP and CACP should add this cost to cost C2 while considering them for MSP. It is opined that further study is required on risk margin.

Projection of Cost

The cost of production and yield of a crop are not known at the time of announcement of MSP for any given season. The cost data is available with 2-3 years' lag. For instance, for the MSP announced for marketing year 2014-15, the COC data in final form will be available upto year 2011-12. Some lag is obvious. Thus, CACP projects cost data for year "T" based on the base data of year T-3 using rate of inflation in different inputs. In doing so, CACP assumes that Fixed Cost does not change in the short run and uses a complicated methodology for constructing Composite Variable Input Index (CVII). The components of this index are: human labour (HL), bullock labour (BL), machine labour (ML), seeds, fertilizers, manure, insecticides and irrigation charges. This method has two shortcomings as under:

- In an inflationary economy it is not justified to assume that fixed cost will not change in 2-3 years.
- If technological change is not happening, then growth in productivity necessitates input per unit of output (I/O) to rise, implying increase in real average cost over time.

It is quite complex to deal with the second limitation, but it is very easy to address the first one. The solution for this is to raise fixed cost component of cost C2 according to rate of inflation in relevant variables included in fixed cost. The most important component of fixed cost is land rent. The other components are interest on fixed and working capital and depreciation of farm assets. The committee proposes following methodology to project various items of fixed cost:

As regards the projection of interest on fixed capital, it may be mentioned that this component can be easily calculated by accounting for the period for which the loan is taken as under:

- Interest and depreciation on fixed capital should be projected by raising them at the rate of inflation in construction material.
- Interest on working capital should be projected by raising it in accordance with composite variable input index.
- Land rent should be projected by raising it by index number (WPI) of agricultural commodities which is the main determinant of variation in land rent.

However, on this issue CACP expressed that fixed cost comprises of interest on fixed capital and rental value of owned land. As regards depreciation on fixed capital and interest on

working capital (which is not the part of fixed cost) are separately projected. So, essentially rental value of owned land and interest on fixed capital has to be considered for projection of fixed cost. It was observed by CACP that rental value of owned land as projected by following the suggestion made by the Committee turns out to be much lower than the corresponding actual. The Committee suggests that CACP may separately explore devising a suitable methodology for projecting the fixed cost in a manner that is close to the actual.

Averaging Cost

There are very large variations in cost across states and across farmers within a state. The CACP uses average of cost of sample farmers in all the states to nationally represent cost of production. This implies that about half of the farmers will have actual cost above the average and the remaining half below the average level. As the level of MSP is generally higher than the average of cost C2, the per cent of farmers whose cost is not covered by MSP is lower than 50%. According to a CACP working paper MSP covered C2 cost of 96 percent of sugarcane production, 94 percent of barley, 93 percent of paddy, 92 percent of R & M and 88 percent of wheat production in year 2010-11. Suggestions have been made in the past to take bulk line cost rather than average cost for fixation of MSP; some have asked for the high cost state to be used as a base cost for fixing MSP (Item 4.6 of the CACP 2008-09 report). The guiding principle for this should be to strike a balance between efficiency consideration and maximum coverage of farmers. One rule of thumb is to take average of efficiency criterion that uses arithmetic mean and maximum coverage of farmers' i.e 100%. This will imply that bulk line cost comprising 75% [(50+100)/2] of farmers should be used to represent cost C2. DES at present generates state-wise cost estimates for all the crops based on established estimation procedure. However in order to have a maximum coverage of farmers, DES may examine the bulk line cost as suggested by the Committee.

Sample Size and Sampling Method

Reliability and representativeness of cost estimates depend heavily on sample size and methodology used for selection of sample farmers. Following suggestions are made to improve representativeness and reliability of COC data:

1. Under the Comprehensive Scheme for Cost of Cultivation of Principal Crops, operated by the Directorate of Economics and Statistics (DES), at present one sample village is selected from each selected tehsil/block. The Committee suggests that two villages should be selected in place of one village from each selected tehsil/block for wide coverage of

sample villages. This will require increase of resources and man power commensurate with increase in sample size to strengthen the system of collection of cost data from the farmers.

2. Operational holdings should be classified into 3 size classes, namely, less than 1 ha, 1-2 ha and more than 2 ha, in place of present classification of 5 size classes and number of operational holdings selected from each size class should be 3, 2 and 1 respectively i.e., six units from each village.

3. (a) The Committee observed shortcomings in the present method of sample selection where, the sample holdings selected for some of the minor crops are very small. The Committee felt that selection of sample with probability proportional to area under minor crops is expected to overcome this problem. On this the Committee suggests of modifying the existing sampling design by introducing sub-strata under each zone one as Normal strata (for major crops) and other as Minor crop strata while selecting the tehsils/blocks, and can be further extended while selecting villages within the selected tehsil.

   (b) For Cereals, Pulses and Oilseeds, at State level only those crops may be selected under these groups so that they should cover at least 90% of the total area under these groups respectively. For Jute, Coconut and Sugarcane, major growing states may be selected in such a way that at least 90% of the area at all India level is covered. This may increase the chances of reporting significant number of operational holdings growing minor crops in the sample. This sampling methodology approach may be tried on a pilot basis before final adoption.

4. To improve the quality of primary data collected and proper field supervision the ratio of field supervisor and field investigator /field man should be 1:6 in place of present 1:10 ratio. However more field supervisor will be required for which necessary provision should be made.

5. The present system of collecting information from the selected farmers/holdings for the three year block period should remain unchanged. In order to reduce the time lag of providing cost estimates generated under CS, an updated software need to be in place at the earliest.

6. For generating reliable COC estimates state wise the committee recommend state-wise minimum sample size of 300 operational holdings. It is, however, mentioned that with the increase in sample size the sampling error will come down but the non-sampling error may go up.

7. At present, 23 crops are considered for fixing MSP/FRP and among these crops, some crops have become rare/minor crops in terms of availability and the present sampling design is primarily targeting the major crops, as result in the sample insignificant (sometimes nil) observations for these rare crops are getting selected and reported. This fact has already been noted by the Committee.

8. The suggestion to select the crops with PPS with area as rare crop area may not be the best feasible solution. If PPS, with area under minor crop as size measure, is adopted the process may exclude many blocks/tehsil from selection, as rare crops are generally not cultivated in all the Blocks/Tehsils. Instead, committee may consider the suggestion of modifying the existing sampling design by introducing sub-strata under each Zone as Normal (for Major Crops) – strata and Rare crop strata while selecting the Tehsil/Blocks, it can be extended further while selecting Villages within the selected Tehsil. This will definitely increase the chances of reporting reasonable number of operational holdings growing such rare crops. The sampling methodology may be tried on pilot basis before adapting.

Tariff, Taxes, Credit and Market

The committee feels that structure of tariff, taxes, credit and market have strong effect on cost of production and output prices and consequently on farm income.

Tariffs

India has already sharply lowered actual tariff on import of farm produce. Though India's bound tariffs are strong to provide safeguards against cheap imports, the actual rates are quite low. India needs to follow a policy of variable tariff involving rise in duty when international prices are high and low rate of duty when international prices are low. Further, heavy and persistent dependence on import of those commodities which are largely produced in the country should be reduced.

India's oilseed sector has suffered serious setback due to import liberalization. Because of low and declining tariff on vegetable oils, their domestic prices have remained adverse to Indian producers and suppressed supply response. The price parity going against oilseeds needs to be addressed adequately. Because of this, India is not able to harness potential of dryland and marginal areas in raising oilseed output. The Committee suggests that tariff on both crude as well as refined vegetable oils are fixed appropriately keeping in view farmer's interest and to allow oilseed sector to acquire competitive edge.

On export side, India does not have tariff regime on agricultural exports. Agri-food exports are regulated by arbitrary non-tariff barriers. Whenever domestic prices tend to go high, agricultural exports are restricted. Country has been frequently stopping export of various agricultural products, whenever there was a fear of high increase in domestic prices. A closer scrutiny of import and export policy indicate that India accorded very high priority to maintain price stability, and a surge in domestic prices often led to more liberalized import and restrictions on exports. This gives the impression that, in most cases, interest of consumers has been placed above the interest of producers. The committee emphasizes that CACP must be

consulted on tariff and trade policy for agricultural commodities and its producer-centric recommendations should be valued.

Agricultural Credit

With the increased commercialization of agriculture and increase in use of modern inputs, the amount and share of purchased inputs in agricultural production is increasing rapidly. Besides, private investments in different types of assets like irrigation equipments, farm machinery and land improvements are also required to increase or improve the efficiency of production and to maintain growth in agricultural output. Farmers' own resources are not adequate to meet working capital and fixed capital requirement of agriculture. Therefore, farmers have to borrow from external sources to meet these requirements. Unlike industry, agriculture sector does not have access to market equity for raising resources and farmers have to borrow credit either from institutional sources or non institutional sources like money lenders. Loans from private sources, though very common, are often exploitative; available at very high rates and the borrowers from such sources often fall into debt trap. In order to meet the credit requirement of agriculture sector and to reduce dependence of farmers on money lenders and other private sources several steps have been undertaken after 1970 to increase flow of institutional credit to agriculture. As a result of various steps taken by the government, flow of institutional credit to agriculture sector has seen tremendous growth.

Despite the increase in supply of institutional credit, cultivator households are not able to come out of the clutches of money lenders and other non-institutional agencies. This calls for initiating measures to check financial exclusion of large percent of small and marginal farmers (including tenant cultivators and sharecroppers) from institutional financial system. A large number of farms are managed by women farmers but land ownership invariably remains in the name of male members of the family. Women farmers without land ownership title cannot get agricultural credit from institutional sources. Another serious problem with institutional finance is uneven flow of agriculture credit across States and Regions. Even within States, there are sharp differences between credit flow to developed regions, regions with greater access to physical infrastructure or regions closer to urban Centers as compared to under-developed districts or regions.

Comprehensive measures are needed in terms of innovative products and services to increase access to institutional credit. Complex documentation processes and high transaction cost in taking loans needs to be urgently addressed. It is highly desirable to provide Kisan Credit Card to all the farmers in the country and to raise its limit from time to time. There should be some

control and regulation on usury and broad terms and conditions for agricultural loans from money lenders and other private sources should be brought into force.

The Committee suggests that for each state, some minimum limit for supply of institutional credit needs to be maintained. It recommends that at least 25 per cent of value of agricultural output should be supplied as short term loan each year in every state. This figure corresponds to value of non labour inputs in farming.

Market

Agricultural markets suffer from inefficiency, disconnect between prices received by the producers and prices paid by consumers for agricultural products, fragmented and long marketing channels, poor infrastructure and policy distortions. It is also found that in total value added in production and marketing, the share of value-added in post-harvest segment is rising and that in production is falling. In some cases, value addition in marketing is larger than value addition in production. With farm size getting smaller day by day, income from agriculture produce can be improved by enabling the farmers to get a share of value-added in marketing by developing and strengthening marketing mechanisms which include producers and their collectives as partners; special focus can be on women farmers' collectives given the concentration of most women workers in agriculture. Urgent reforms are needed in agricultural marketing to achieve such goals and to address conditions prevailing in agricultural markets.

The best marketing model for producers and consumers are those where producers sell directly to consumers either as individual or as some sort of organization. Such models have been developed in some states like Apni Mandi in Punjab and Haryana, Rythu Bazaar in Andhra Pradesh and Uzhavar Sandhai in Tamil Nadu. Under these arrangements, farmers are allowed to sell their produce as retail to consumers in the towns on selected days and time without intermediaries, with express transportation facilities provided by the government in the case of Rythu Bazaar for instance. The scale of operation of these marketing arrangements is quite low as only farmers located in the vicinity of big towns can benefit from this form of marketing. Similarly, there is the Hopcoms experience in Karnataka. Such innovative marketing should be promoted on large scale.

Demand pattern of agricultural commodities both at consumer and industry level has been changing rapidly towards processed products, quality products and specific traits. These changes favour integrated supply chain rather than conventional marketing channels, assured market rather than open market and specific produce rather than generic one. Such supply

chains also offer a tremendous scope to reduce middlemen's margin. A well-functioning supply chain can reduce the cost of marketing by linking farmers more closely to processing firms and consumers and guide the production to meet changing consumer preferences for quantity, quality, variety, and food safety. Modern supply chain also often involves private standards and their enforcement - that help coordinate supply chains by standardizing product requirements for suppliers over many regions or countries, enhancing efficiency and lowering transaction costs. The concept of supply chain is more beneficial to small holders who dominate India's agriculture. It is also suggested to promote institution of "integrator" to assemble small produce and sell it in market on behalf of producers or own behalf.

A few experiments such as direct procurement backed with technical support have benefited the farmers immensely. These indicate that participation of cooperatives and private sector firms in marketing of agricultural produce under specific environment can help farmers. This calls for a thorough review of the existing agricultural marketing policies and implementing change that will bring the producer closer to the consumer.

Given the vastness and diversity of Indian agriculture, the country requires multiple approaches including APMC mechanism, new models, and upscaling of successful experiences like cooperative milk marketing, along with organised retail to impart efficiency, competitiveness and modernisation of agricultural marketing. All states, in particular, need to promote producers' associations, producers companies, co-operative marketing societies to improve bargaining power of producers in marketing and to raise the share of producers in value addition in marketing, which is getting bigger and bigger. Most of the reforms needed in agricultural marketing are proposed in model APMC Act. The states must implement model Act in true spirit of competitiveness without diluting it to serve interest of particular group. This will certainly pave the way for direct marketing, vertical co-ordination through contract farming, provide alternative options to producers for sale of produce and create competitive environment for services which are currently a monopoly of Agricultural Produce Market Committee.

While increased participation of private sector in agricultural marketing is desirable, the country also needs strong presence and participation of public sector and marketing models based on participation of producers, like cooperatives, producer companies and producer associations. Public sector in agriculture and food marketing is as much important for competitiveness, as is private sector needed for improving efficiency. Public sector is also essential to serve larger social goal of maintaining price stability through market operations. Private sector has absolutely no interest in price stability, it rather benefits from it. This is strongly borne by the global experience of last six years. It shows that in the wake of supply shocks, countries like India, with strong presence of public sector in staple food, have

succeeded in protecting its market against price volatility, whereas, many developing countries, without public sector presence in food staples, have suffered seriously from price shocks and volatility.

Any Other Related Matter

Modern and progressive agriculture requires use of modern inputs like quality seed, fertilizer, agro-chemicals, and efficient farm machinery. Farmers would go for use of these inputs if these are available at reasonable prices, at right time and at right place and are of desired quality. Incidentally, most of the public debate on agriculture policy concentrates on output prices and much attention is not paid to input prices except to subsidies. In order to promote use of modern inputs to boost production and attain growth, it is essential to ensure competitive environment for supply of farm inputs.

Seed is the most crucial input in agriculture. Till a few years back, public sector was the dominant supplier of quality seed. With increase in demand for quality seed and with the increase in participation of private sector in seed production being witnessed now, its price has become an important issue. There are reports of abnormally high price being charged by some private companies for seed. This kind of incidence is going to increase with commercialization of molecular biology, which has opened new avenue for manipulating genetic traits in plants and animals. This trend would entail not only production of seed but also other inputs such as herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers. This is giving rise to type of industry with monopoly control over certain traits and products. Thus, in order to check market power of one or a few firms to dictate input price there is a need to have regulatory authority on input prices. There is also lot of confusion around pricing of fertilizer. In order to deal with all such issues, the country need to set up a "Farm Input Competition and Regulatory Authority" with sufficient powers to deal with issues related to farm inputs. *However, DES is of the view that in a market driven economy the input prices are also driven by the market forces; hence prices of such inputs cannot be subject to a regulatory mechanism. There are various other regulatory authorities are operational such as Competition Commission of India which addresses the issue of competition.*

Problem of spurious inputs is assuming menacing proportion. The reports of supply of spurious inputs (seeds, fertilizer and chemicals) are moving day by day from almost all parts of the country. Spurious inputs not only cause loss in terms of expenditure on them but they

cause much bigger loss in terms of return to the whole investment in production besides causing loss of opportunity to earn living and income. There is a need for promoting competition in input industry and for strong system of quality monitoring.

Recommendations

Methodological issues:

1. Under the Comprehensive Scheme for Cost of Cultivation of Principal Crops, operated by the Directorate of Economics and Statistics (DES), at present one sample village is selected from each selected tehsil/block. The Committee suggests that two villages should be selected in place of one village from each selected tehsil/block for wide coverage of sample villages. This will require increase of resources and man power commensurate with increase in sample size to strengthen the system of collection of cost data from the farmers.

2. Operational holdings should be classified into 3 size classes, namely, less than 1 ha, 1-2 ha and more than 2 ha, in place of present classification of 5 size classes and number of operational holdings selected from each size class should be 3, 2 and 1 respectively i.e., six units from each village.

3. (a) The Committee observed shortcomings in the present method of sample selection where, the sample holdings selected for some of the minor crops are very small. The Committee felt that selection of sample with probability proportional to area under minor crops is expected to overcome this problem. On this the Committee suggests of modifying the existing sampling design by introducing sub-strata under each zone one as Normal strata (for major crops) and other as Minor crop strata while selecting the tehsils/blocks, and can be further extended while selecting villages within the selected tehsil.

   (b) For Cereals, Pulses and Oilseeds, at State level only those crops may be selected under these groups so that they should cover at least 90% of the total area under these groups respectively. For Jute, Coconut and Sugarcane, major growing states may be selected in such a way that at least 90% of the area at all India level is covered. This may increase the chances of reporting significant number of operational holdings growing minor crops in the sample. This sampling methodology approach may be tried on a pilot basis before final adoption.

4. To improve the quality of primary data collected and proper field supervision the ratio of field supervisor and field investigator/field man should be 1:6 in place of present 1:10 ratio. However more field supervisor will be required for thorough scrutiny of data collected due to increase in sample size for which necessary provision should be made.

5. The present system of collecting information from the selected farmers/holdings for the three year block period should remain unchanged. In order to reduce the time lag of providing cost estimates generated under CS, an updated software need to be in place at the earliest.

6. Counting of time spent by farmers in production alone and valuing it at the wage rate of ordinary labour is gross undervaluation of the farmer's time, whereas it is felt that farmers should be treated as expert in agricultural work. The committee suggests that head of the family engaged in farming should be valued at skilled wage rates. In addition, cost C2 should be raised by 10 percent to account for the risk premium and managerial charges of a farmer. *However, DES differed on this issue and alternatively suggested that 10 percent of the paid-out cost including family labour (A2+FL) should be added to cost A2+FL to account for the managerial charges of a farmer.*

7. Interest on working capital should be estimated for whole, not half, of the period of crop season and should be on actual interest paid out by sample farmers.

8. Land rental values should be based on actual rates prevailing in the sample villages or with the sample farmers in particular without any ceilings fixed on the same.

9. Animal labour charges should be the full year's cost taken as is, apportioned over the crop area served, as per the reporting from the sample farmers and not only as per the number of hours that the bullock pair works. Though DES informed that cost is computed like this only, however, if there is any deviation from this method that should be avoided.

10. Post harvest costs like cleaning, grading, drying, packaging, marketing and transport of produce to market, incurred by farmers, should form part of COC. It is also recommended that appropriate risk margin should be added to arrive at C2 cost of cultivation. *However, on this issue DES outlined that COC is ex-farm costs and calculated in Rs/ha, whereas marketing & transport costs are post-harvest costs and calculated in Rs/qtl. Therefore, such costs cannot be the part of COC.* Alternatively it is suggested that all these costs should be indicated separately while forwarding costs estimates to CACP and CACP should add these cost to cost C2 while considering them for MSP.

11. The committee observes that various items of fixed cost are not projected for the year for which MSP is announced. Therefore, it recommends that Interest and depreciation on fixed capital should be projected by raising them at the rate of inflation in construction material. Interest on working capital should be projected by raising it in accordance with composite variable input index. Land rent should be projected by raising it by index number (WPI) of agricultural commodities which is the main determinant of variation in land rent. However, on this issue CACP expressed that fixed cost comprises of interest on fixed capital and rental value of owned land. As regards depreciation on fixed capital and interest on working capital (which is not the part of fixed cost) are separately projected. So essentially rental value of owned land and interest on fixed capital has to be considered for projection of fixed cost. The Committee suggests that CACP may separately explore devising a suitable methodology for projecting the fixed cost in a manner that is close to the actual.

12. In taking average of the cost at the national level, the guiding principle should be to strike a balance between efficiency consideration and maximum coverage of farmers. One rule of thumb is take average of efficiency criterion that uses arithmetic mean and maximum coverage of farmers i.e. 100%. This will imply that bulk line cost comprising 75% [(50+100)/2] of farmers is used to represent cost C2. DES at present generates state-wise cost estimates for all the crops based on established estimation procedure. However in order to have a maximum coverage of farmers, DES may examine the bulk line cost as suggested by the Committee.

Mandate of CACP:

13. CACP is the appropriate body to articulate the concerns of farmers and agriculture sector and to advance interest of farmers. The Committee recommends that the role of CACP should be expanded and it should be renamed as "Commission on Agricultural Costs, Prices and Policies". The CACP, based on data collected in the Comprehensive Scheme to begin with, should put out information on farm incomes for different crop complexes and specific categories of farmers, and make recommendations related to farm incomes and remunerative prices. The CACP should be equipped with 4 senior level experts with sufficient support staff to undertake analysis of various policies on food, agriculture and farmers. The Commission should submit quarterly report on state of agriculture, food, prices and state of farmers with list of policy recommendations to respond to the emerging situation. The quarterly report should be placed before the Cabinet like CACP report on Price Policy for considering its implementation. *However, DES is of the view that policy formulation is mandate of the Government and this cannot be assigned to the Commission and suggests that the various policy inputs provided by the CACP under various price policy reports submitted by the CACP are given due consideration by the Government which includes both price and non price recommendations.*

14. CACP should monitor farm harvest prices in the season for all important crops in all the states to oversee that farmers are not paid price below MSP, lending legal sanctity to the MSP recommended and declared. If prices fall below statutory MSP, CACP should make immediate recommendation to government to address the situation.

15. As price guarantee cannot be ensured through procurement everywhere, mechanisms like Deficiency Price payment or Price Insurance should be put in place for price surety for all the crops for which MSP is declared. *However, DES pointed out that Deficiency Price Payment as a price guarantee is not appropriate for India as this is prevalent in the countries where only one or two crops are covered. Deficiency Pric e mechanism cannot be adopted for India where 23 crops are covered under MSP. Instead there is a need to strengthen the procurement to ensure MSP for the farmers whenever the market price falls below the MSP. According to DES, the procurement for ensuring MSP should be primary responsibility of the State Governments which may undertake procurement whenever required.*

16. The CACP should publish annual review of prices and farm incomes, as well as various policies affecting agriculture and farmers which should be placed in the Parliament in budget session. However, DES is of the view that there is no need for placing the report of CACP in the Parliament. The various recommendations on various issues relating to CACP are discussed in detail in the Parliamentary Committee on Agriculture, Parliamentary Standing Committee on Demand and Grants and other such Committees.

17. With the trade liberalization and globalization, instruments of trade policy have started affecting farm prices strongly. The tariff and export and import decisions are generally taken based on interest of consumers. The committee feels that CACP should be involved and present its recommendations in all trade policy decisions.

Other Issues:

18. The committee feels that structure of tariff, taxes, credit and market have strong effect on cost of production and output prices and consequently on farm income. Therefore, these aspects also need to be considered beside price aspect to achieve goal of price policy.

19. Heavy and persistent dependence on import of food items like edible oils which are largely produced in the country should be reduced. The Committee suggests that tariff on both crude as well as refined vegetable oils are fixed appropriately keeping in view farmer's interest and to allow oilseed sector to acquire competitive edge. The committee emphasizes

that CACP must be consulted on tariff and trade policy and its recommendation should be valued.

20. Unlike industry, agriculture sector does not have access to market equity for raising resources and farmers have to borrow credit either from institutional sources or non institutional sources like money lenders which are often exploitative. The Committee suggests that for each state some minimum limit for supply of institutional credit, with distinct limits set for different categories of farmers, need to be maintained. It recommends that at least 25 per cent of value of agricultural output should be supplied as short term loan each year in every state. This figure corresponds to share of various inputs (excluding labour) value of output of crop and livestock sector.

21. Markets for agri-produce are not evolving with other developments. The demand pattern of agricultural commodities both at consumer and industry level has been changing rapidly towards processed products, quality product and specific traits. This calls for a thorough review of the existing agricultural marketing policies and implementing changes that will bring the producer closer to the consumer and also leave larger shares of the retail price accruing to the producer.

22. Given the vastness and diversity of Indian agriculture, the country requires multiple approaches including APMC mechanism, new models, and upscaling of successful experiences like cooperative milk marketing, along with organised retail to impart efficiency, competiveness and modernisation to agricultural marketing. All states, in particular, need to promote producers association, producers companies, co-operative marketing societies to improve bargaining power of producers in marketing and to raise the share of producers in value addition in marketing.

23. In order to promote use of certain inputs to boost production and attain growth, it is essential to ensure competitive environment for supply of farm input. Price and quality of seed and other inputs have become contentious issues. In order to deal with all such issues the country need to set up a "Farm Input Competition and Regulatory Authority" with sufficient powers to deal with pricing, availability and quality aspects of farm inputs. *However, DES is of the view that in a market driven economy the input prices are also driven by the market forces; hence prices of such inputs cannot be subject to a regulatory mechanism. There are various other regulatory authorities are operational such as Competition Commission of India which addresses the issue of competition.*

अनुलग्नक I

Annexure I

Constitution of The Committee And Terms of Reference (ToR)

No. A-49011/2/2013-EA
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture and Cooperation
Krishi Bhawan, New Delhi

Dated: 1st April, 2013

ORDER

Subject : Constitution of Committee to examine Methodological Issues in Fixing Minimum Support Prices

*****

With the approval of the Competent Authority, a Committee has been constituted to examine the methodological issues in fixing minimum support prices. The Composition of the Committee is as under:

Composition

1.	Director, NCAP	Chairman
2.	JS(EA)	Member
3.	Secretary, CACP	Member
4.	State Govt. Representatives:	
	(i) Representative from Govt. of Andhra Pradesh	Member
	(ii) Representative from Govt. of Uttar Pradesh	Member
5.	Representatives of Indian Coordination Committee of Farmers' Movements:	
	Shri Ajmer Singh Lakhowal	Member
	Shri Rakesh Tikait	Member
	Shri Yadhuvir Singh	Member
	Shri K.T.Gangadhar	Member
	Ms. Kavita Kuruganti	Member
6.	Prof. R.S. Deshpande, ISEC	Member
7.	Dr. U.C. Sud, IASRI	Member
8.	Adviser (Cost), DES	Member
9.	Adviser (FE), DES	Member
10.	DDG, SDRD, NSSO	Member
11.	Adviser (Cost), CACP	Member Secretary

Terms of Reference

a) To examine the existing mandate of the Commission for Agricultural Costs and Prices and suggest whether – by way of a measure of response to the rapidly changing external environment arising in the wake of liberalization, privatization and globalization – there is need to reposition the Commission in terms of its mandate and remit.

b) To examine the existing cost concepts for the purpose of fixing minimum support prices and suggest various factors including cost of transportation, marketing, processing, storage etc. to determine MSP. Besides, the Committee may also analyse the appropriateness of existing methods followed in imputing the value of (i) family labour; (ii) rental value of land; (iii) interest on capital; (iv) depreciation on fixed items such as tractors, bullocks etc. and recommend measures for improvement so as to make them more realistic.

c) To examine the existing structure of tariff, taxes, credit, market etc. and to suggest various measures to make it most competitive and remunerative to the farmers in the wake of trade liberalization and globalization and also to encourage diversified agricultural growth.

d) To examine any other related and relevant matters that are important for improving the system.

2. TA/DA will be admissible to the Non-official Members of the Committee as per rules.

3. The Committee may submit its report as early as possible.

(A.K.Arora)
Under Secretary (EA)
Govt. of India

F.No. A – 49011/2/2013 - EA
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation

Krishi Bhawan, New Delhi 110001
Dated the 17th April, 2013

ADDENDUM

Sub.: **Constitution of Committee to examine Methodological Issues in Fixing Minimum Support Prices**

Government of India, Ministry of Agriculture order No. A-49011/2/2013-EA dated 1st April, 2013 is amended to add the following name in the Composition therein below S.No. 5 as a representative of the Indian Coordination Committee of Farmers' Movements :-

Shri Chokki Nanjunda Swamy - Member

(A.K. Arora)
Under Secretary to the Government of India
23387962

To
1. Chairman and all Members of the Committee
2. Member Secretary of the Committee
3. Shri Chokki Nanjunda Swamy, National Coordinator, 636, Ideal Layout Homes, Raja Rajeswari Nagar, Bangalore.

Copy for information to:-
1. PPS to Secretary, Department of Agriculture & Cooperation
2. PPS to Pr. Adviser, Department of Agriculture & Cooperation
3. PS to JS (EA)

अनुलग्नक II

Annexure II

Minutes of Meetings

Subject: Minutes of the First meeting of the Committee to examine Methodological issues in Fixing Minimum Support Prices

First Meeting of the Committee set up by Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture to examine Methodological issues in Fixing Minimum Support Prices was held on 9th May, 2013 at 3 PM in Room No. 138, Mahalanobis Committee Room, Krishi Bhawan, New Delhi. The meeting was chaired by Dr. Ramesh Chand, (Director, National Centre for Agricultural Economics & Policy). The List of Participants is enclosed in Annexure– I.

First of all, in the beginning, S.R. Joshi, Adviser, CACP and Member Secretary of the Committee welcomed all the Members of the Committee for participating in the Meeting. Since this was the first meeting, Member Secretary requested all the Hon'ble Members of the Committee to introduce themself before starting the formal discussion. He stated that the Committee has been asked to examine methodological issues as per Terms of Reference.

After the introduction, Chairman expressed his pleasure over the composition of the meeting as the Members of the Committee belong to different fields relating to agriculture. He said that each item covered under terms of reference of the committee will be discussed in separate meetings. He reiterated to have a fresh look into the methodological issues in the rapidly changing economic scenario and external environment of the world. He expressed that the items covered under the MSP regime are less and said determining MSP is purely technical process and the issue should be seen broadly. The Chairman requested for detailed presentation from Directorate of Economics & Statistics (DES) and Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for determining cost to support improvement, if any. Apart from this, he also requested DES to invite few representatives from State Agencies/Universities who are collecting data to give presentation on their data supplied under Comprehensive Scheme along with request to invite other concerned agencies to give their presentation to make under understand their issues.

Shri Yadhuvir Singh, Representative of Indian Coordination Committee of Farmers' Movement expressed that farming is no more a profitable activity. And, the credit on farmers is increasing because his purchasing power is declining. The agricultural prices do not rise at par with other products sold in the market, the cost fixation formula is partially based on Western Policy Scheme & USA methodology where subsidy is provided to farmers to meet the deficit confronted by them but in our price policy this provision has been left over so he emphasized that either fully European methodology be adopted on our own methodology be designed as per Indian agriculture scenario. Dr

Ramesh Chand intervened and said that service sector has gone up four fold as compared to agriculture sector and this should benefit farm production and farm families.

Ms Kavita Kuruganti Farmers' representative expressed that the terms of reference of this committee is same as that of Alagh Committee consitituted in the past on the same subject and this committee should redesign its Terms of Reference. She also reiterated that MSP determining formula should be reviewed so that farmers should get realization for their produce, on this Chairman intervened that MSP is notional not statutory. He apprised that deficiency price payment is made in USA to compensate the farmers if they get less price for their agricultural produce. Also, she raised the point that in 2008, MSP was announced in such a way that it covered high cost states against the present reality.

Sh. Bhagat Singh, a farmers' representative raised the issue that producers' security is completely ignored by declaring less MSP for the members to understand the methodological issued before any observation on the issues. Also, the market considers MSP as Maximum Support Price instead of Minimum Support Price so the farmer in the open market realizes price even less than MSP. He asked for a solution in this concern. DES was requested to invite state officials and other officials to make presentation on the methodology adopted in the field to collect the data by the field level. Requirements to make market competitive because ultimate prosperity of farmers will not come through MSP alone.

Dr. Sud, Director, Indian Agricultural Statistics Research Institute (IASRI) said that 8100 sample size covering 27 crops across 19 states is very less. It should be enhanced and a survey for collecting data should have broadened perspective like Agriculture Census.

Ms. Kavita expressed that CACP yield derivation is query based whereas, states derive it from crop cutting experiments and thus Cost of Production comes low. She reiterated yield derivation should be viewed in detail to increase Cost of Production. Main focus of the Commission should be on producers and price depreciation should be given to farmers.

Shri K.T. Gangadhar farmers' representative expressed that Agricultrual universities are not providing proper data to govt. and govt. is not taking care of producers but of consumers and hence farmers are unable to pay their debts.

The Chairman concluded with the comments not to be fully dependent on MSP, famers should also grow horticulture, more profitable crops which are not covered under MSP regime for getting profit.

For the members to understand the methodological issues before any observations, the following decisions were taken:

1) DES was requested to invite few representatives from State Agencies/Universities who are collecting data to give presentation on their data supplied under Comprehensive Scheme along with request to invite other concerned agencies to give their presentation to make understand their issues;

2) DES was requested to give presentation on the methodology of Comprehensive Scheme for collecting cost of production;

3) CACP may be requested to give a presentation on methodology adopted for MSPs.

Subject: Minutes of the Second meeting of the Expert Committee to examine Methodological issues in Fixing Minimum Support Prices

The second meeting of the Expert Committee set up by Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture to examine Methodological issues in Fixing Minimum Support Prices was held on 7th August, 2013 at 10.30 AM in Room No. 142, Acharya Jagdish Chandra Bose Hall Committee Room, Krishi Bhavan, New Delhi. The meeting was chaired by Dr. Ramesh Chand, (Director, National Centre for Agricultural Economics & Policy Research). The List of Participants is enclosed in Annexure– I.

Chairman welcomed all the Members and participants present in the meeting and Member Secretary of the Committee briefed about the presentations to be given by Directorate of Economics and Statistics, DAC and implementing agencies of Madhya Pradesh & Gujarat state.

Sh. T.K. Dutta, Adviser, DES started with the outline of the survey and apprised that the data collection started since 1971, under the Comprehensive Scheme (CS), previously which was known as Farm Survey. He also briefed on objectives of the survey under CS and stated how crop wise, state wise estimates are generated for the use of CACP for determining MSP covering 19 major states. He further expressed that, the crop complex method is adopted for covering 27 crops in 810 Tehsils comprising of 8100 holdings. These surveys are conducted through implementing agencies/universities. Total samples are pre fixed and are generally selected for a block of three years and number of holdings generally do not change over the years. The data collection mechanism consists of 40 RTs (schedules) which involves all agricultural activities as well as inputs both in physical and monetary terms to be filled in by field man on weekly/monthly/yearly basis, the data is scrutinized, validated and refined before passing it to DES. Sh. Dutta further apprised that FARMAP Software used currently is a binary DOS based programme being used since 1991, to utilize and analyse the cost data. The software is obsolete and not user friendly and efforts are being taken to introduce new system so that field man can directly send the information to centre.

In the meanwhile, Member from Punjab Sh. Lakhwal suggested that skilled labour rates be considered for imputing family labour rate. Dr V.K. Singh, Director, Agriculture statistics from UP raised the issue of land rent, and said that land rent varies from land to land due to different yields. Yields may be over estimated or underestimated as reported by farmer as per his requirement on which Sh. Dutta replied that derived yield rates are taken into account which is generated through the system of the programming. Dr. S.S. Kalamkar, Hon. Director, Cost of Cultivation scheme S.P. University, Gujarat told that land rent is different for irrigated and unirrigated land in Gujarat. Shri Dutta reported that there is a time lag in data supplying to CACP due to delay in reporting of data from state govts; state govts. collects data after completion of agricultural year. Dr. Sud, Director, IASRI, opined that there is no use of collecting data every year considering inputs used do not change every year on which

Chairman apprised that cost is done on projection basis and agriculture is faced by fluctuations in output, prices etc. it does not make any difference if projections be made two yrs before or 5 years before, however, data can be made representative if year to year fluctuations can be captured in cost with some in built mechanism in the estimates. Ms Kavitha also emphasized on data correctness. She also expressed that farmers should be assured a good income even in a disaster year on which Sh. Yudhvir Singh, Member suggested some mechanism should be introduced in cost to capture the fluctuations occurred in agriculture.

The second presentation was given by Dr. Sahu, Field Officer, JNKVV, Madhya Pradesh. He apprised that cost data is collected with accuracy using Cost accounting method taking into account both physical & monitory terms and then sent to DES after scrutiny and validation, he explained about how the records are compiled by the staff. He suggested, that sample size be increased proportionately. He reported that condition of small and marginal farmers is very poor and farmers are requesting for some incentive in terms of farm inputs in lieu of questioning him daily for filling schedule. He requested if some incentive is given to farmers then the data quality will definitely improve.

The next presentation was given by Dr. S.S. Kalamkar, Hon. Director, CS, S.P. University, Gujarat. He informed that cost accounting method is used for data collection. Cotton and groundnut are major crops grown in the state. Dr. Kalamkar, replied on the question of correctness of data that data is maintained accurately. Dr. Sud intervened and expressed concern over the data quality generated under agricultural census on which chairman intervened and said such data could have some limitations but it cannot be dismissed for use.

Though no formal presentation was given by U.P., Shri V.K. Singh, Director, Agriculture Statistics from UP Govt. apprised that the survey is done by district agricultural deptt., sample is selected on the basis of proportionate area under the crop. He expressed that rent of land is computed on the basis of value of output reported by farmer for six months, the yield reported by farmers is also cross checked by crop cutting experiments. He also reported that transportation and marketing costs along with managerial cost are also included in total cost of crop, risk cost & profit per quintal @ 25% on cereals and 30% on pulses is also given. A sub committee comprising of Minister, Principal Secretary, mandi directors decides cost of crops under kharif, rabi etc.

Chairman intervened and told that crops are being sold 20% to 40% lower than MSP in UP mandis. Member Secretary Shri Joshi informed that wheat procurement in UP is very low as compared to other states and why farmers take their produce to adjoining states for selling their produce, this issue also needs to be taken into consideration. Shri Rakesh Tikait, one of the farmer's representatives, expressed his concern over functioning of agricultural officers of UP state. He suggested, that, profitable MSP with assured procurement should be given to farmers to increase production and suggested no crops should be procured below MSP. He further expressed that farmers are shifting to towns due to deficit of finance & farming not being a profitable activity any more. Farmer representatives from Andhra Pradesh and Punjab expressed their views on MSP and cost and they also suggested for better MSP with assured procurement to improve deteriorating conditions of small and marginal farmers.

The post lunch session started with the presentation of Sh. S.R. Joshi, Adviser, on Terms of Reference, mandate and composition of the Commission along with likely impact of MSP on rest of the economy.

He apprised that CACP also recommends non price measures like subsidy on fertilizers, irrigation packages to lessen the burden on the farmers. He briefed about NBS policy and reiterated that subsidy on fertilizers be stablised in such a manner that policy mechanism facilitate the beneficiary at ground level. He made aware of the drip irrigation and fertigation techniques adopted by Maharashtra state to apply it for cost effectiveness and also informed that the recommendation of the Commission are submitted to DAC which are circulated to state governments and concerned Ministries for their views/suggestions. He requested for any suggestions for further improvement on the above issues.

After this Ms. Kavitha, Member expressed her views that social security should be provided to farmers alongwith assured MSP, and further said that MSP is unable to cover the cost of production of major states therefore, C2 of high cost states should be considered as one of the factors for determining MSP instead of All India weighted average C2. She further spoke about the land rent which is taken as 1/5th of the output value as uniform formula for this, rental value is not properly reflected, the committee should look into managerial cost for farmers, whether interest on credit is taken from institutional or some other source, she also suggested for looking for option whether risk cost (@ 1% margin) can be included in cost.

Ms. Kavitha also highlighted that, the MSP is becoming procurement price and pointed out that according to agriculture census data 9.2 million cultivators have been reduced in the last decade.

At last, Chairman stated that during the last 20-25years in seven to eight occasions price increase has been given in MSP He stated that farmers are not always at the loss as the rent of land is included in the cost is a profit to them. Also, he requested that a copy of instruction manual of Comprehensive Scheme along with a crop wise list of sample households from whom cost of cultivation (COC) is collected may be provided to the members of the committee to understand the method, coverage and concepts involved in data collection and composition. He stated that some new instruments are available for direct data entry i.e. computer at farm level. He suggested that new devices such as CAPI (Computer Assisted Personal Interview) need to be explored and used to process COC data instead of old FARMAP package. He also made detailed discussion on evaluation of family labour (FL) stressing on a point that FL need to be imputed at the wage rate of skilled labour rather than unskilled labour. He expressed that commission is not an autonomous body and questioned the present strength of the Commission suggesting to have interaction with Chairman CACP to know the views of the Commission on the structure, constitution, mandate and terms of reference of CACP.

Finally Member Secretary gave the concluding remarks thanking all the members of the Committee for fruitful discussion.

Subject: Minutes of the Third meeting of the Expert Committee to examine Methodological issues in Fixing Minimum Support Prices

The third meeting of the Expert Committee set up by Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture to examine Methodological issues in Fixing Minimum Support Prices was

held on 13th November, 2013 at 11 a.m. in Room No. 142, Acharya Jagdish Chandra Bose Hall Committee Room, Krishi Bhawan, New Delhi. The meeting was chaired by Dr. Ramesh Chand, Director, NCAP (National Centre for Agricultural Economics & Policy Research). The List of Participants is enclosed in Annexure– I.

Firstly, Sh. S.R. Joshi, Member Secretary (MS) of the committee welcomed all the members & participants present in the meeting. He briefed the committee members on various issues discussed in the last meeting viz., the presentations made on cost of cultivation survey under Comprehensive Scheme (CS) (by Directorate of Economics & Statistics (DES) and its implementing agencies of states of Madhya Pradesh and Gujarat) and cost projection methodology by CACP. He stressed on adoption of uniform methodology for collection of data under the CS. MS reiterated that time has come up to firm up discussions on the different methodological issues related to the recommendations of the committee to strengthen the MSP mechanism. He welcomed any other issue to be raised by the members of the committee along with issue pertaining to strengthening and improvement of cost estimates under the CS.

After this, Sh. Ramesh Chand, Chairman welcomed all the participants in the meeting and expressed that the committee has broadly three Terms of Reference i.e. review of existing mandate of CACP, the methodology adopted by it while recommending MSP along with status of CACP in current economic scenario and cost perceptions, specially for assessment of imputed costs, interest on working capital etc. and third one is recommendation on import/export policies tariff/regulations, taxes on agriculture, credit market related policies which can effect farmers income and prices. Chairman discussed on the agenda paper given by DES and expressed that Dr. Sud, Director, IASRI can give better views on statistical issues pertaining to cost calculation methodology viz., sampling design, sample size, weights etc. Chairman continued with the issue of farm labour and interest on working capital and suggested that, imputation of farm labour should be as per the skilled labour rate and interest rate may be taken as actual rate of credit taken by farmer from any institute or money lender. Sh. T.K. Dutta, Adviser, DES added that review on economical and operational part, taxes, markets and other concepts have been undertaken in the past, but no review has been undertaken on statistical aspect since inception of Comprehensive Scheme and discussion by all the members in the Committee.

Sh. Dutta highlighted that reliability of CS data has been questioned from time to time along with inadequacy of sample size. He added for some crops' sample size is high as compared to other crops and sampling error is not calculated which restricts efficacy and precision of CS cost estimates and this is the right time to discuss on the improvement of statistical aspect of CS methodology. He proposed to increase the sample size along with increase in man power to handle this. Ms Kavitha, the farmer representative assured equal participation of farmers' representatives in technical aspects and Terms of Reference of the Committee. Chairman requested Dr. Sud to give his detailed view on sampling design and techniques in the next meeting as being an important statistical aspect, he also expressed that a sub group of the committee may also discuss later the statistical issues of CS methodology.

Sh. Sinha, JS, DAC, M/o Agriculture apprised the Committee that an agreement has been signed with Space Application Centre, Ahmedabad, to use satellite imagining to assess production and productivity of 12 to 13 crops, irrespective of sample size whenever, it is needed in any state of the country. On this

issue Sh. Dutta expressed it will not help in generating cost estimates. Chairman highlighted that, CACP while recommending MSP takes several factors into account apart from cost. Sometimes MSP recommended is not very high due to high level of buffer stocks but still these are remunerative besides buffer stocks and adverse international situation. He reiterated to look the past MSPs fixed/announced which were as per the requirement of the economy and to align domestic prices with international prices. The chairman informed that he discussed the issue of fixing MSP based solely on Cost of Production with former and present chairman CACP. If MSP is to be fixed solely based on COP then there was no need for a professional body like CACP. Cost based price fixation can be done mechanically. Moreover, actual experinec shows that other factors were often considered to benefit farmers and many a times MSP was raised based on other factors irrespective of cost. He sought and welcomed independent views of the members on this.

Sh. Pasha Patil, the farmer representative from Maharashtra expressed that CACP should work in the sole interest of farmers and expressed that there is a wide difference in the MSP declared for cotton by the central govt. and cost assessed by their state govt., and also expressed dissatisfaction over the data quality collected by universities for CS. Sh. Yudhvir Singh, the farmer representative intervened and expressed that animal labour costs should be assessed for the whole year on which Sh. Dutta, Adviser, DES apprised that expenses incurred even for upkeep of bullock for the entire year is taken into account and all India average is taken for assessing bullock labour cost. Chairman supported that animal labour cost is calculated scientifically and actual wages of bullock labour is taken wherever, it is available. In the meanwhile, Sh. Rakesh Tikait the farmer representative brought forward the issue of loan/ credit to farmers and said that they are not getting adequate prices for their produce hence bound to either live in depression or divert towards other profession. Sh. Patil added that depreciation of land value should also be taken into account as land loses its nutrient value with time and also pointed that incidence of crop failure which occurs once in every five years should also be taken into account while calculating cost. On this Chairman intervened and suggested some risk premium mechanism should be devised to cover this as the estimates are generated in advance and also felt that there is need to look into the divergence of cost estimates generated by states and DES. Chairman said that suggestions of Sh. Lokhwal the farmer representative for considering state average yield and not the sample yield for determining cost of production may also be taken into account.

Chairman expressed that the benefit of MSP is taken by 30% of farmers only, so mere suggesting MSP is not sufficient, its implementation part should also be a point of concern. Chairman expressed his concern over the shrinking role of CACP and gave opinion that CACP should have bigger role and should be given powers to take decision on the matters related to trade and tariff policy, marketing policies, recommendations on interest rate, credit, risk, taxation on farming, agricultural land policy, other agriculture matters. To do these things CACP should have experts on trade, marketing, credit, production and other agricultural matters. The chairman suggested renaming CACP as Commission for Agricultural Costs Prices and Policies.

On this issue Sh. Rakesh Tikait gave his view that there should be agriculture cabinet or any similar kind of Committee on agriculture who can work out on regular basis on policies related to agriculture viz., import/export policies, distribution of fertiliser subsidy, linkage of MGNREGA scheme to agricultural labour ,monitoring of MSP so that no procurement should be made below MSP. On this

Ms. Kavitha added that CACP should have legal mandate having sole mandate of protecting farmers' interest. Sh. Gangadhar another farmer representative suggested that NABARD and credit policies should be reviewed and some sort of subsidy should be given to farmers. He also emphasized that credit facilities to farmers should be strengthened so that they should not be forced to take loans from money lenders at higher interest rates. .

Sh. Sud expressed that increasing sample size will benefit only major crops which is not in favour of crop complex approach and if selection of minor crop area is done through unequal probability selection, it will cover even those areas having minor crops.

In the concluding session Chairman briefed the deficiency price payment mechanism followed in United States and suggested for a system under which farmers should register their quantity to be marketed in market committee. If the prices of that crop falls below representative market, deficiency prices should be paid to farmers to ensure a minimum guaranteed price to him. He added MSP could not be effective without this mechanism except for commodities procured for PDS, and this mechanism will ensure farmers producing other agricultural commodities like pulses and which is WTO compliant also as it provides some sort of insurance and requested farmers representatives to think over this. Chairman suggested MSP should be fixed but procurement price should be variable. It was also suggested by some members that procurement should be made on the monthly basis which will lessen burden on the procurement agencies and provide better prices to farmers he further added farmers are well equipped to maintain a sizeable stock with them till the procurement is made.

Member Secretary concluded with vote of thanks to the Chairman and all the members present in the meeting.

Subject: Minutes of the Fourth meeting of the Expert Committee to Examine Methodological issues in Fixing Minimum Support Prices

The fourth meeting of the Expert Committee set up by Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture to examine Methodological issues in Fixing Minimum Support Prices was held on 1st August, 2014 at 11.00 AM in Room No. 142, Acharya Jagdish Chandra Bose Hall Committee Room, Krishi Bhawan, New Delhi. The meeting was chaired by Dr. Ramesh Chand, Director, NCAP (National Centre for Agricultural Economics & Policy Research). The Secretary, DAC, M/o Agriculture also grace the meeting with his presence and valued suggestions. The List of Participants is enclosed in Annexure– I.

Member Secretary Sh. S.R. Joshi welcomed all the members of the Committee and briefed on the issues discussed in the last meeting. After that, first draft report of the committee, a communication received on various points received from the Maharashtra Government and a note on technical issues proposed by DES were circulated among all the members of the Committee for discussion on each aspect which are associated with the TOR of the Committee.

After this, Chairman welcomed all the participants in the meeting. To begin with, Chairman briefly discussed the issues proposed by DES and then requested Sh. T.K. Dutta, Adviser, DES to throw some light on the structure, functioning and methodology of data collection viz., sample size, no. of size classes, selection of crops, choice of weights presently under the CS scheme. Sh. Dutta highlighted crop complex approach undertaken for computing data under Comprehensive Scheme and expressed that reliability of CS data has been questioned from time to time along with inadequacy of sample size and proposed that the sample size can be doubled by increasing more villages in a tehsil which is currently covering one village comprising of 10 farmers each, he suggested that weekly or fortnightly assessment should be done for farming activity by the data collector/field man to cover maximum sample holdings, as there is shortage of staff, also the farmer does not make expenses on daily basis, on this Chairman intervened and supported the current practice of daily assessment by the field man against the issue of shortage of staff he expressed that, the issue can be referred to the Govt. for increasing the staff strength. Sh. Dutta, opined that, Dr. Sud, Director, IASRI can give better views on sampling design and techniques, on this Dr. Sud expressed in the current scheme for some crops' sample size is high as compared to other crops, sampling error is not calculated, which restricts efficacy and precision of CS cost estimates and he disagreed on increasing sample size to double. He requested for the data to arrive at any conclusion on the sample size increase.

Afterwards, a small conversation set out on the points given by Maharashtra Government. Ms. Kavitha, farmer representative said regarding sampling that sample size should be decided in proportion and percentage of the farm holdings Dr. Sud intervened and said that variability aspects should be taken care of by adopting single crop approach rather than crop complex approach with probability proportion to area to capture the major crops covered under sampling, on this Chairman suggested Sh. Dutta and Dr. Sud to give their collective suggestions on the technical aspects of sampling. Ms. Kavitha added that yield under irrigated and unirrigated areas should also be included under sampling. On which Chairman informed that data is representative of both the areas.

Subsequently, the Secretary, Deptt. of Agriculture & Cooperation, M/o Agriculture joined the meeting, Chairman apprised him of the sampling issues being discussed in the meeting. After hearing the comments, Secretary presented his views elaborately and cleared some facets of the sample selection. Dr. Sud added in the discussion that sampling error increases as the sample size increases and this factor should also be taken care of. Ms. Kavitha added that, the yield reported in the Crop Cutting Experiments (CCE's) is low against that reported in the CS scheme and if the former ones are used it will lead to increase in the cost of production on which Dr. Sud intervened and said there is no significant difference in yields reported in the two surveys. The Chairman emphasized that, CS data is more realistic as compared to CCE's data. Issues on land rental value and assessment of family labour rates were also discussed.

Consequently, the draft report circulated by Chairman was discussed; He suggested that, the committee should strictly adhere to the Terms of Reference (TOR) given to this Committee prior to making its recommendations before the govt. He expressed to modify the existing mandate of CACP and mentioned TOR should have goals of national interests keeping in view achievability, interest of farming community, farm mechanization, misbalance in farming and non farming sectors, profitability of farming, agricultural infrastructure, import prices etc. CACP should recommend some price

deficiency mechanism to ensure an appropriate compensation and price assurance to farmer. He added that there should be an alternative price mechanism of procurement, difference price payment or price assurance.

Next he commented on trade policy, tariff structure and including expert from each field in CACP i.e. by expanding the present structure and TOR of CACP so that it should function as a representative in a recognized way for farmers. CACP should be Commission for Agricultural Costs prices and policies since prices play a major role. He proposed 10% margin on C2 cost which should be given to farmer as managerial, entrepreneurial cost, risk insurance etc., rent on owned land should be taken on the prevalent land rate in the village, interest on owned fixed capital, working capital should be taken at the prevalent rates, weighted interest rates should be taken as farmers borrow loan from govt. as well as private institutions. Also, interest on working capital should not be taken for half of the cropping period rather should be for the whole period and the costs of processing, transportation and marketing should also be included in C2 cost. Presently CACP is only projecting variable cost and not the fixed cost on this Chairman suggested for projecting fixed cost, interest and depreciation can be projected by using inflation rates in construction material and interest on working capital by using WPI of agricultural commodities. Mandi taxes subject was also discussed in detail; however, Chairman gave opinion that, it is a state subject. In the end, Chairman asked all the members of the Committee to give their opinion/suggestions on different issues discussed during the meeting so as to incorporate them in the draft report of the Committee. The meeting ended with thanks to the chair.

*****

List of Officers Associated with the Report of the Committee

Cost Division, CACP

1. Ms. Nidhi Satija,
   Assistant Director
2. Dr. Bhavik Lukka,
   Economic Officer
3. Sh. S.K. Srivastava,
   Senior Statistical Officer

EA Division, DAC

1. Sh. A. K. Arora,
   Under Secretary
2. Sh. N.P. Mathur,
   Section Officer
3. Sh. Sandeep Biswas,
   Assistant